

अवैध खनन के आरोपों पर हाई कोर्ट सख्त

जालंधर, मोगा और लुधियाना की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी, मौजूदा स्थिति और कार्रवाई का ब्योरा भी तलब

■ खनन गतिविधियों पर प्रशासन की निगरानी व नियमन पर उठाए सवाल

■ अदालत पहले भी जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी दे चुकी है

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के जालंधर, मोगा और लुधियाना जिलों में कथित अवैध खनन से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

अदालत ने संबंधित जिलों में खनन गतिविधियों की मौजूदा स्थिति, कथित अवैध उत्खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई और जिम्मेदार लोगों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। अदालत की निगरानी में चल रहे इन मामलों ने पंजाब में खनन गतिविधियों पर प्रशासन की निगरानी और नियमन को लेकर फिर सवाल खड़े किए हैं।

मामलों में सामने आए आरोपों के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में नदियों और अन्य स्थानों से रेत और बकरी के अवैध उत्खनन की शिकायतें की

गई हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा रहा है कि अवैध खनन से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, बल्कि पर्यावरण और नदी तंत्र पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग मामलों में यह पक्ष रखा जाता रहा है कि संबंधित क्षेत्रों में वैध खनन, गाद निकालने या सरकारी परियोजनाओं के तहत स्वीकृत गतिविधियों को अवैध खनन से अलग करके देखा जाना चाहिए।

लुधियाना पर भी नजर: लुधियाना और जालंधर से जुड़े खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय मंजूरियों और खनन स्थलों के नियमन को लेकर सरकारी स्तर पर दस्तावेजी प्रक्रिया पहले से चलती रही है।

जिला स्तर पर खनन स्थलों की पहचान और सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। ऐसे में हाई कोर्ट की ओर से मांगी गई स्टेट्स रिपोर्ट में कथित अवैध गतिविधियों के साथ-साथ वैध खनन स्थलों की स्थिति और निगरानी व्यवस्था का भी ब्योरा महत्वपूर्ण हो सकता है।



रिपोर्ट से तय होगी अगली दिशा

अब पंजाब सरकार और संबंधित जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर अदालत की अगली कार्रवाई निर्भर करेगी। यदि रिपोर्ट में अनियमितता या अवैध उत्खनन की पुष्टि होती है तो अदालत जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे सकती है। वहीं, प्रशासन को यह भी स्पष्ट करना होगा कि अवैध खनन रोकने के लिए निगरानी, जांच और प्रवर्तन की व्यवस्था कितनी प्रभावी है। अदालत की लगातार सख्ती से साफ है कि केवल कागजी कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी; जमीनी स्तर पर रोकथाम और जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी।

चंडीगढ़ में साइबर अपराध समन्वय केंद्र की शुरुआत

कार्रवाई और जांच में बेहतर तालमेल पर जोर

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

चंडीगढ़ में साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य साइबर ठगी और अन्य ऑनलाइन अपराधों की जांच में विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। यह पहल केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की व्यवस्था से भी जुड़ी है।

चंडीगढ़ में आई4सी की संयुक्त साइबर समन्वय टीम अंतरराष्ट्रीय और बहु-क्षेत्राधिकार वाले मामलों में पुलिस को सहयोग देती है।

केंद्र के माध्यम से साइबर अपराध से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण, सॉडिग खातों की पहचान और ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क पर कार्रवाई में समन्वय बढ़ाने की उम्मीद है। चंडीगढ़ पुलिस ने आई4सी से मिले इनपुट के आधार पर साइबर ठगी में इस्तेमाल कथित म्यूल खातों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। वित्तीय साइबर ठगी के पीड़ितों को तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराने और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

हिमाचल: स्टडी लीव के वेतन में डीए भी मिलेगा

कर्मचारियों को सैलरी के साथ एचआरए भी

समर न्यूज़ | शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की स्टडी लीव से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। वित्त विभाग ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) नियम, 1972 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत अब स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को अवकाश के दौरान लीव सैलरी के साथ महंगाई भत्ता (डीए) और मकान किराया भत्ता (एचआरए) भी मिलेगा। यह संशोधन 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा।

संशोधित नियम-56 के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी देश या विदेश में उच्च अध्ययन के लिए स्टडी लीव पर जाता है, तो उसे अवकाश पर जाने से पहले मिलने वाला पूरा वेतन स्टडी लीव अवधि के दौरान भी मिलता रहेगा। इससे पहले डीए और एचआरए का लाभ उपलब्ध नहीं था। सरकार ने इसके साथ एक शर्त भी तय की है। यदि कर्मचारी स्टडी लीव के दौरान किसी प्रकार की स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या पार्ट-टाइम नौकरी का पारिश्रमिक नहीं ले रहा है, तो उसे इसका प्रमाण-पत्र देना होगा।

सतलुज में खनन पर भी सख्ती

इससे पहले हाई कोर्ट ने सतलुज नदी क्षेत्र में कथित अवैध रेत खनन को लेकर पंजाब सरकार से जवाब तलब किया था। अदालत ने अधिकारियों को कार्रवाई में लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी थी और अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित उपयुक्त को व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड के साथ पेश होने के संकेत दिए थे। मामला ग्रामीणों की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा था, जिसमें सतलुज के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध खनन का आरोप लगाया गया था।

जालंधर में पहले भी तय की जा चुकी है जिम्मेदारी

जालंधर जिले में अवैध खनन को लेकर हाई कोर्ट पहले भी प्रशासन को कड़े निर्देश दे चुका है। एक पुराने मामले में अदालत ने उपयुक्त को विस्तृत जांच कर अवैध रूप से निकाले गए खनिज की मात्रा निर्धारित करने और दोषी लोगों से उसकी कीमत की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि जिले में अवैध खनन की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए और संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही तय हो।

मोगा में योजना के दुरुपयोग का मामला

मोगा जिले में भी बाढ़ प्रभावित किसानों को खेतों में जमा रेत हटाने की अनुमति देने वाली योजना के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आ चुका है। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने इस छूट की आड़ में व्यावसायिक स्तर पर अवैध खनन किया। इस मामले में खनन कानून के तहत कार्रवाई की गई थी। घटनाक्रम से स्पष्ट है कि सरकार को राहत और वैध खनन की अनुमति वाली योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी निगरानी बढ़ानी पड़ रही है।

पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में कहा- ऐसे हथियारों का इस्तेमाल केवल असाधारण परिस्थितियों में हो

पैलेट से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराएं: सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए लोगों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार को प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (आरएफ) द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को भी कहा है।

मामला 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पैलेट से घायल लोगों की शिकायतों से जुड़ा है। अधिकारिक रिकॉर्ड में आरएफ द्वारा एंटी-रायट गन से प्लास्टिक पैलेट के दो राउंड चलाए जाने का उल्लेख सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति में पैलेट गन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं



है, लेकिन इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। अदालत का जोर इस बात पर रहा कि बल प्रयोग की परिस्थितियों और इस्तेमाल किए गए हथियारों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।

अदालत के निर्देश के बाद घायल प्रदर्शनकारियों के उपचार और घटना

से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने पर जोर बढ़ गया है। इस मामले में कम से कम तीन लोगों के पैलेट से घायल होने की जानकारी सामने आई थी। आरएफ की भूमिका और कार्रवाई के क्रम की जांच भी की जा रही है।

जनरल डायरी में डीसीपी के निर्देश का जिक्र: सीजेपी के 20 जुलाई के 'संसद चलो' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर पुलिस की जनरल डायरी में दर्ज एक विवरण सामने आने के बाद विवाद फिर गहरा गया है। पुलिस रिकॉर्ड के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, जंतर-मंतर क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक डीसीपी स्तर के अधिकारी के निर्देश पर रैपिड एक्शन फोर्स (आरएफ) के जवान ने एंटी-

रायट गन से दो राउंड फायर किए थे। एंटी-रायट गन को इसी श्रेणी के गैर-घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

जनरल डायरी में दर्ज विवरण के अनुसार, कार्रवाई के दौरान आरएफ ने आंसू गैस और अन्य गैर-घातक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया। रिकॉर्ड में प्लास्टिक पैलेट हवाले दो राउंड चलाए जाने का उल्लेख है। यह विवरण एक आरएफ अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, संबंधित अधिकारी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। विवाद के बीच आरएफ ने कानून-व्यवस्था से जुड़ी कार्रवाई में अगले आदेश तक पैलेट गन और कुछ अन्य उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है।

आईएस अग्रवाल की जमानत का सीबीआई ने किया विरोध

657 करोड़ के बैंक घोटाले में जांच एजेंसी ने बताई कथित भूमिका, अधिकारी ने आरोप नकारे

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

657 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक-एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में गिरफ्तार हरियाणा के आ ई ए ए स अधिकारी पंकज अग्रवाल की जमानत याचिका का केंद्रीय जांच ब्यूरो

(सीबीआई) ने विरोध किया है। जांच एजेंसी ने अदालत में कहा कि मामले में उनकी भूमिका की जांच अभी जारी है और उन्हें राहत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। सीबीआई का आरोप है कि सरकारी खातों से धन के कथित दुरुपयोग में अग्रवाल की भूमिका रही। वहीं अग्रवाल ने अदालत में कहा है कि उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों के प्रस्तावों पर प्रशासनिक मंजूरी दी थी और किसी तरह की रिश्तदारी नहीं ली।

पेज 1 एंकर स्टोरी

छेहरटा-वाराणसी के बीच नई ट्रेन से धार्मिक जुड़ाव के साथ दो राज्यों की सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत

मिशन-2027: पंजाब को वाराणसी से जोड़ेगी ‘संत रविदास एक्सप्रेस’

रविदासिया समुदाय के बीच इसे लंबे समय से चली आ रही मांग की पूर्ति के रूप में देखा जा रहा

समर न्यूज़ | जालंधर

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच छेहरटा (अमृतसर) और वाराणसी के बीच शुरू हुई 'संत रविदास एक्सप्रेस' राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर कैट से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

यह सेवा पंजाब और उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख धार्मिक केंद्रों को सीधे जोड़ती है और खास तौर पर गुरु रविदास के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रेलवे बोर्ड से मंजूर यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी। ट्रेन का संचालन छेहरटा से बुधवार, शुक्रवार और

रविवार तथा वाराणसी से गुरुवार, शनिवार और सोमवार को होगा। करीब 1,139 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन लगभग 22 घंटे में तय करेगी। इसके मार्ग में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला कैट, सहरनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और जौनपुर समेत कई प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।

पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 32 प्रतिशत है, जो देश के राज्यों में सबसे अधिक हिस्सेदारी में से एक है। दोआबा क्षेत्र में रविदासिया समुदाय का विशेष प्रभाव माना जाता है। ऐसे में नई ट्रेन को केवल परिवहन सुविधा के बजाय व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में भी देखा जा रहा है। भाजपा के लिए पंजाब में 2027 का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है और पार्टी लंबे समय



से राज्य में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, ट्रेन की शुरुआत को सीधे चुनावी कदम के रूप में देखना राजनीतिक व्याख्या है। आधिकारिक तौर पर इसका प्रमुख उद्देश्य धार्मिक यात्रियों और आम यात्रियों के लिए पंजाब-उत्तर प्रदेश के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। ट्रेन से धार्मिक पर्यटन, कारोबार

और दोनों राज्यों के बीच नियमित यात्रियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

नाम और रूट को लेकर बदलाव: शुरुआत में ट्रेन को 'संत रविदास एक्सप्रेस' नाम से प्रचारित किया गया था। बाद में इसके नाम में बदलाव की जानकारी सामने आई और इसे 'सौर गोवर्धनपुर वाराणसी एक्सप्रेस' के नाम से भी संदर्भित

650वें प्रकाश पर्व से पहले अहम कदम

नई रेल सेवा ऐसे समय शुरू हुई है, जब गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व को लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है। वाराणसी का सौर गोवर्धनपुर गुरु रविदास की जन्मस्थली के रूप में रविदासिया समुदाय के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। पंजाब सरकार भी 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सालभर कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में नई ट्रेन से पंजाब से वाराणसी जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधी रेल सुविधा मिलने की उम्मीद है।

सियासी संदेश से ज्यादा धार्मिक जुड़ाव पर जोर

नई ट्रेन को लेकर रविदासिया समुदाय में उत्साह है। इसे वाराणसी स्थित गुरु रविदास जन्मस्थान और पंजाब के प्रमुख धार्मिक केंद्रों के बीच संपर्क मजबूत करने वाली सेवा के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के जालंधर दौरे और ट्रेन के उद्घाटन को भाजपा की पंजाब में राजनीतिक सक्रियता के संदर्भ में भी देखा जा रहा है, लेकिन ट्रेन की उपयोगिता का असर आने वाले महीनों में इसके यात्रियों और श्रद्धालुओं को संख्या से भी सामने आएगा।

किया गया। ट्रेन का मूल रूट छेहरटा-अमृतसर से वाराणसी के बीच है, इसलिए इसे केवल 'वाराणसी-

जालंधर' ट्रेन कहना तकनीकी रूप से सही नहीं होगा। जालंधर कैट से इसका उद्घाटन किया गया था।

मेरी रसोई योजना के तहत पंजाब में 33.8 लाख राशन किट बांटीं

चंडीगढ़ | पंजाब सरकार की 'मेरी रसोई' योजना के तहत राज्य में अब तक करीब 33.8 लाख राशन किट वितरित किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

सरकार ने करीब 40.48 लाख पात्र परिवारों को हर तिमाही राशन किट देने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत प्रत्येक किट में दाल, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल दिया जाता है। यह सामग्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले गेहूं के अतिरिक्त है।

सरकार का कहना है कि योजना से परिवारों के रसोई खर्च का बोझ कम करने के साथ पोषण और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी। पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 'मेरी रसोई' योजना के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

चन्नी-वडिंग को करीब लाने की जिम्मेदारी नरेश अरोड़ा को, सुलह की कोशिशें तेज कांग्रेस ने वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष और चन्नी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाए रखा

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से जारी अंदरूनी खींचतान को खत्म करने और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं।

पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, राजनीतिक रणनीतिकार नरेश अरोड़ा को दोनों नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, इस भूमिका को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस ने हाल ही में पंजाब के लिए अपने चुनावी नेतृत्व ढांचे में संतुलन साधने की कोशिश की है। पार्टी ने राजा वडिंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा

बेअदबी विरोधी कानून पर जत्थेदार गड़गज्ज ने कहा- फैसले में गंभीरता नहीं दिखाई गई

श्री अकाल तख्त साहिब की आपत्तियों पर सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग

एजेंसी| अमृतसर

पंजाब के बेअदबी कानून को लेकर अकाल तख्त और राज्य सरकार के बीच मतभेद का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने सरकार की ओर से संशोधनों पर अपेक्षित तेजी नहीं दिखाए जाने पर चिंता जताई है।

उनका कहना है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान और सत्कार से जुड़े मामलों को केवल सांसारिक कानून के दायरे में नहीं देखा जा सकता। इस मामले में धार्मिक मर्यादा और पंथ की भावनाओं को भी सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। जुनू में अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए सिख विधायकों और मंत्रियों के सामने कानून की कई

कर्नाटक मॉडल का हवाला

नरेश अरोड़ा को लेकर पार्टी हलकों में यह चर्चा है कि उन्होंने कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर पैदा हुए मतभेदों के दौरान संवाद और राजनीतिक प्रबंधन में भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के लिए कर्नाटक का अनुभव महत्वपूर्ण है, जहां नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लंबे समय तक दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच खींचतान रही। हालांकि, पंजाब में अरोड़ा की मौजूदा भूमिका को लेकर पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

दिल्ली में चन्नी, रंधावा व वडिंग की बैठक से हलचल नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति और संगठन को मजबूत करना बताया गया, लेकिन प्रदेश नेतृत्व को लेकर मतभेद भी सामने आए।

है, जबकि चन्नी को चुनाव अभियान समिति की कमान सौंपी गई है। प्रताप सिंह बाजवा को विधानसभा में विश्व

के नेता की जिम्मेदारी जारी रखने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

2027 की तैयारी पर फोकस: चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को एकजुट रखना है। पार्टी नेतृत्व मानता है कि गुटबाजी का असर चुनावी प्रदर्शन पर पड़ सकता है। ऐसे में चन्नी और वडिंग के बीच बेहतर तालमेल बनाना केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकताओं में शामिल है। नरेश अरोड़ा की कथित भूमिका को भी इसी व्यापक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

एकजुटता दिखाने की कोशिश: कांग्रेस ने नेतृत्व के दोनों धड़ों को अलग-अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर संतुलन साधने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर गुटबाजी कम करने में कितनी सफल रहती है। पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल नेताओं को एक मंच पर लाना है।

बीएलएम गर्ल्स कॉलेज में हवन के साथ नए सत्र की शुरुआत

जगदीश लाल | नवांशहर
समर न्यूज़

बीएलएम गर्ल्स कॉलेज, नवांशहर में गुरु पूर्णिमा और नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विद्यार्थियों की प्रगति, अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और उज्ज्वल भविष्य के लिए आहुतियां दी गईं।

कॉलेज की प्रिंसिपल तरनप्रीत कौर वालिया ने बताया कि कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव विनोद भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ आरके आर्य कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. पुनीत अनेजा, डब्ल्यूएल आर्य स्कूल की प्रिंसिपल आरती कालिया, सुशील पुरी, अक्षय तेजपाल, अचला भल्ला और अमर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति

सीएम भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 2020 में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मामले की एफआईआर रद्द कर दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मामले में अपराध के प्रथमदृष्टया पर्याप्त आरोप हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई और पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रशासन के अनुसार, आरोपी मौके पर मौजूद था और उसका नाम एफआईआर में दर्ज है। दलील दी गई कि गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य द्वारा किया गया क्रूर अन्य सदस्यों पर भी लागू हो सकता है।

पंजाब बंद का कई जिलों में असर, बाजार रहे बंद सफाई कर्मियों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन बरनाला की घटना के खिलाफ वाल्मीकि समाज व कर्मचारी संगठनों का आह्वान

समर न्यूज़। चंडीगढ़

पंजाब में सफाई कर्मचारियों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बुलाए गए बंद का गुरुवार को कई जिलों में असर देखने को मिला। अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, पटियाला और पठानकोट समेत कई शहरों में बाजार बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह रोष प्रदर्शन किए और सरकार से बरनाला की घटना के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया।

बंद के दौरान कई शहरों में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों ने बाजारों में घूमकर दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों के हाथों में डंडे होने और लोगों को बाजार बंद करने के लिए मजबूर करने के वीडियो भी सामने आए हैं, हालांकि

पंजाब बंद के आह्वान पर नवांशहर जिला पूर्ण बंद बरनाला कांड के दोषियों पर एससी एसटी एक्ट लगाने तक हड़ताल जारी रहेगी

बंगा, राहों, बलाचौर, नवांशहर, मुकुंदपुर, जाड़ला रहा बंद

जगदीश लाल | नवांशहर
समर न्यूज़

पंजाब सफाई यूनियन की तरफ से बरनाला में हड़ताल दौरान पुलिस के डीएसपी सुखजीत सिंह बैस के ईशारे पर हुई मारपीट के खिलाफ पंजाब बंद के आह्वान पर नवांशहर पूर्ण बंद रहा। नवांशहर के बंगा, राहों, बलाचौर, नवांशहर, मुकुंदपुर, जाड़ला रहा बंद रहा। वाल्मीकि समुदाय से सूरज, खोसला, सनी बघानिया, जतिंदर अबरोल ने कहा कि पंजाब सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है।

सफाई कर्मचारियों का धरना हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक डीएसपी पर एससीएसटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होती। उधर, उन्हीं आरोप लगाया कि सरकार उनके समाज में गुप्त बाजी कर रही है, जिसे साजिश को सफल न

मणिपुर के नगा बहुल इलाके में फिर गोलीबारी, 1 की मौत

एजेंसी | इंपाल

मणिपुर के नोने जिले के नगा बहुल इलाके में सुरक्षा बलों और स्थानीय नगा विलेज गार्ड के बीच गोलीबारी में एक विलेज गार्ड की मौत हो गई, जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा इकाई के दो जवान घायल हो गए। एक अन्य विलेज गार्ड के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। घटना बिटियांग (लाफोक) गांव के पास हुई। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

यह घटना उस समय हुई जब सुरक्षा बल इलाके में अभियान चला रहे थे। गोलीबारी कैसे शुरू हुई, इसे लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं। स्थानीय पक्ष का आरोप है कि कोबरा जवानों की ओर से गोली चलाए जाने के बाद जवाबी फायरिंग हुई। मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

मानसून

केदारनाथ मार्ग पर आवाजाही प्रभावित, श्रद्धालुओं को रोका

जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हालात

एजेंसी | नई दिल्ली

देश के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता के बीच भारी बारिश का दौर जारी है। जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क मार्ग बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं।

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भी खराब मौसम और भूस्खलन के कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रियों को सावधानी बरतने और मौसम साफ होने तक सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि उत्तराखंड में भी तेज बारिश और गरज-चमक को लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में

पंजाब/देश



इन घटनाओं की व्यापक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाई।

बरनाला की घटना से शुरू हुआ विवाद: बंद का आह्वान बरनाला में सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज के विरोध में किया गया था। घटना के बाद पुलिस बंद कार्रवाई पर सवाल उठे और मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। सरकार की ओर से कार्रवाई के बाद

पंजाब बंद के आह्वान पर नवांशहर जिला पूर्ण बंद



होने दिया जाएगा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस प्रदर्शन में चिट्टू अरोड़ा, विजय पूरी, परम खालसा, मखन सिंह ग्रेवाल, बिकरी गिल, जसबीर दीप, भाजपा के विशाल शर्मा, मुनीश अग्निहोत्री, जरसी महलों, जस नवांशहर, बहादर चंद अरोड़ा, निर्मल राजपूत, नम्रता खन्ना, रजनी कंडा, कुलविंदर रसन, राजविंदर लक्की, बलवंत सिंह, मनमोहन गुलाटी, अलावा, दुकानदार यूनियन, व्यापार मंडल, मुस्लिम समुदाय, आंटो यूनियन, रेहड़ी यूनियन, मेडिकल

प्रेक्टिशनर यूनियन ने वाल्मीकि समाज पर बरनाल में हुए लाठीचार्ज की निंदा की। सरकार से आरोपियों पर इस एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई। नवांशहर में बैंक पेट्रोल पंप, सरकारी स्कूल आम खुले। मगर हड़ताल के चलते शहर के बाजार मुख्य रूप में कोठी रोड, शांति नगर, दाना मंडी, गीत भवन रोड, रेलवे रोड, आर्य समाज रोड, घास मंडी, गुलशन बाजार, नवांशहर चंडीगढ़ रोड, बंगा रोडव , सराफा बाजार बंद रहा।

राजा मर्डर केस: सोनम रघुवंशी न्यायिक हिरासत में भेजी गई

-सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर कहा- केवल तकनीकी खामी के आधार पर राहत देना उचित नहीं एजेंसी | शिलांग

राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलांग की अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में पुलिस की जांच जारी है और अभियोजन पक्ष आरोपों से जुड़े साक्ष्य जुटा रहा है। सोमन पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़ी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि केवल तकनीकी खामी के आधार पर किसी आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि गंभीर आपराधिक मामले



में जमानत पर फैसला लेते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। हालांकि, यह टिप्पणी सोनम को शिलांग अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश से अलग न्यायिक घटनाक्रम है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में जांच आगे बढ़ रही है और आरोपियों से पूछताछ तथा उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। आरो सुनवाई के दौरान जांच की प्रगति और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर भी नजर रहेगी। मामले में दोष सिद्ध होना अभी बाकी है और आरोपियों को अदालत के अंतिम फैसले तक कानूनन निर्दोष माना जाता है।

एजेंसी | नई दिल्ली

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार के पास हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की।

प्रदर्शन में कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सांसद शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की। निपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्षी दलों ने सरकार के समक्ष



राम मंदिर चढ़ावा मामले, परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी थी। अयोध्या मामले की जांच में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच का दायरा मंदिर में चढ़ावे की गिनती से जुड़े कर्मचारियों तक बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई है। विशेष जांच दल की जांच में कथित

स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का कहना है कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है और सरकार को इस पर सदन में जवाब देना चाहिए। सरकार की ओर से विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने और विधायी कामकाज में सहयोग की अपील की जाती रही है।

जांच पर भी नजर: राम मंदिर चढ़ावा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल की जांच के बाद मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। जांच में कथित तौर पर चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन से जुड़े नियमों के पालन में खामियों की ओर संकेत किया गया है। मामला न्यायिक स्तर पर भी पहुंचा है, जहां निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया

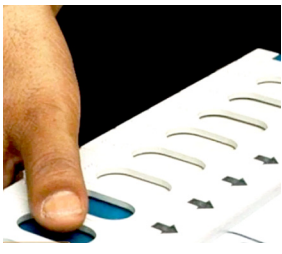
विधानसभा उपचुनाव: बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन सीटों पर मतदान

बांकीपुर में प्रशांत किशोर की सियासी परीक्षा, भाजपा का गढ़ बचाने की चुनौती

एजेंसी | नई दिल्ली

बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। तीनों सीटों पर हुए मतदान के बाद प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। मतगणना 3 अगस्त को होगी। सबसे अधिक राजनीतिक चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट को लेकर रही, जहां जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में हैं और भाजपा अपना मजबूत गढ़ बचाने की कोशिश में है।

बांकीपुर में भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। इस सीट पर भाजपा 1995 से लगातार जीतती आ रही



है। पूर्व विधायक नितिन नबीन यहां से लगातार पांच चुनाव जीत चुके हैं। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उनके विधानसभा से इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव की स्थिति बनी। प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से यह मुकबला जन सुराज के लिए भी अहम हो गया है।

पुलिस कार्रवाई पर किशोर का आरोप: मतदान के दौरान प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जन सुराज से जुड़े कुछ समर्थकों को

पटवारखानों पर ‘कारिंदाराज’

पटवारी नदारद तो निजी लोगों के हाथों में आया सरकारी कामकाज!

फर्द से इंतकाल तक के काम में निजी कारिंदों की कथित दखलंदाजी

राजवीर बक्शी | लुधियाना
समर न्यूज़

शहर के कुछ पटवारखानों में निजी कारिंदों की कथित सक्रियता ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और सरकारी कामकाज की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जिन कार्यालयों में आम लोगों के राजस्व संबंधी काम सरकारी कर्मचारियों की निगरानी में होने चाहिए, वहां निजी व्यक्ति कथित तौर पर बैठकर लोगों के कामकाज में दखल दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि यह व्यवस्था वास्तव में चल रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और प्रशासन की ओर से इस पर निगरानी क्यों नहीं की जा रही।

सूत्रों के मुताबिक, शहर के कुछ पटवारखानों में निजी कारिंदे लंबे समय से सक्रिय हैं। आरोप है कि पटवारखाने पहुंचने वाले लोगों का सामना कई बार पहले इन्हीं निजी कारिंदों से होता है, जबकि संबंधित पटवारी मौके पर मौजूद नहीं मिलते।



सरकारी रिकॉर्ड और मुहरों तक पहुंच

सबसे गंभीर आरोप सरकारी दस्तावेजों और रिकॉर्डों से जुड़े हैं। सूत्रों का दावा है कि कुछ स्थानों पर दस्तावेज तैयार करने से लेकर पटवारी के हस्ताक्षर करवाने तक की प्रक्रिया में निजी लोग सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कुछ पटवारखानों में निजी व्यक्तियों की सरकारी रिकॉर्ड और मुहरों तक कथित पहुंच होने की बातें भी सामने आई हैं। यदि जांच में सरकारी रिकॉर्ड या मुहरों के अनधिकृत इस्तेमाल की पुष्टि होती है तो मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा और राजस्व रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े होंगे।

अब प्रशासन की अगुआई चाहिए

मामला यदि जांच में सही पाया जाता है तो यह केवल कुछ निजी कारिंदों की गतिविधियों का मुद्दा नहीं होगा, बल्कि राजस्व तंत्र की पारदर्शिता, जवाबदेही और सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल बन जाएगा। अब प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि वह शिकायतों की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे और यदि नियमों का उल्लंघन मिला तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे।

आम लोगों के लिए सरकारी और निजी व्यक्ति में फर्क करना मुश्किल

पटवारखानों में आने वाले कई लोगों को यह स्पष्ट नहीं होता कि उनके सामने बैठा व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है या निजी कारिंदा। ऐसे में यदि किसी दस्तावेज में गलती, अनियमितता या कथित फर्जीबाड़ी होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह भी बड़ा सवाल है। राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में पहले भी भ्रष्टाचार और दस्तावेजी अनियमितताओं के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में पटवारखानों में कामकाज की निगरानी और निजी व्यक्तियों की भूमिका की स्पष्टता को लेकर प्रशासन से जवाबदेही की मांग उठना स्वाभाविक है।

अधिकारियों की जानकारी के बावजूद कार्रवाई पर सवाल

सूत्रों का कहना है कि पटवारखानों में निजी कारिंदों की कथित सक्रियता की जानकारी संबंधित एसडीएम और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई जा चुकी है। इसके बावजूद व्यापक स्तर पर जांच या प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। हालांकि, प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि शिकायतें प्रशासन तक पहुंची हैं तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पटवारखानों में निजी व्यक्तियों की क्या भूमिका है और क्या उन्हें सरकारी रिकॉर्ड या दस्तावेजों तक किसी तरह की अधिकृत अथवा अनधिकृत पहुंच हासिल है।

पढ़ाई-रोजगार के लिए विदेश की ओर युवाओं का रुख, रोकने में जुटी सरकार

सरकार का दावा- सरकारी नौकरियों के साथ निजी क्षेत्र, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार पर दिया जा रहा जोर

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

पंजाब में युवाओं का विदेश जाकर पढ़ाई और रोजगार तलाशना पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक और आर्थिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में जाने की चाह रखने वाले युवाओं की संख्या ने राज्य में ‘ब्रेन ड्रेन’ की चिंता बढ़ाई है। विदेश जाने वाले छात्रों, कामगारों और स्थायी रूप से प्रवास करने वालों के आंकड़े अलग-अलग स्रोतों में अलग तरीके से दर्ज होते हैं। फिर भी पंजाब से बड़ी संख्या में युवाओं के बाहर जाने की प्रवृत्ति को लेकर सरकार, शिक्षाविद और सामाजिक

कौशल प्रशिक्षण और उद्योग से जोड़ने की कोशिश

युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार योग्य बनाने के लिए पंजाब कौशल विकास मिशन और रोजगार विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रोजगार पोर्टल पर नौकरी के अलावा कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस दिशा में उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। हाल ही में गुरदासपुर स्थित सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में नए उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फार्मेसी, कृषि और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम शामिल हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने इसे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को उद्योग की जरूरतों से जोड़ने और युवाओं के विदेश जाने की प्रवृत्ति को कम करने की दिशा में एक कदम बताया है।



मंत्री बोले- युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर रहे

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने हालिया पहल के दौरान कहा है कि पंजाब की उच्च शिक्षा को पुराने और केवल सैद्धांतिक ढांचे से निकालकर उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाया जा रहा है। नए पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटरशिप और लाइव प्रोजेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का व्यापक जोर ऐसे संस्थान और पाठ्यक्रम तैयार करने पर है, जहां पंजाब के युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योग से जुड़े अवसर अपने राज्य में ही मिल सकें।

उच्च शिक्षा में विकल्प बढ़ाने पर जोर

ब्रेन ड्रेन का एक पहलू उच्च शिक्षा भी है। विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले युवाओं का एक बड़ा वर्ग इस उम्मीद के साथ बाहर जाता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ रोजगार मिलेगा और स्थायी निवास का रास्ता खुलेगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अनुसार, जनवरी 2025 तक विदेशों में उच्च शिक्षा ले रहे भारतीय छात्रों की संख्या करीब 12.5 लाख आंकी गई थी। इनमें पंजाब के छात्रों की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है। पंजाब सरकार की चुनौती यह है कि विदेश जाने को पूरी तरह रोकना व्यावहारिक लक्ष्य नहीं हो सकता। स्थानीय विश्वविद्यालयों में विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम, अनुसंधान के अवसर, उद्योग आधारित प्रशिक्षण, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और प्रतिस्पर्धी वेतन वाली नौकरियां बढ़ाने की जरूरत है।



विदेश जाने की प्रवृत्ति को अवसर में बदलने की चुनौती

पंजाब के लिए विदेश में बसे लोगों का नेटवर्क केवल ‘ब्रेन ड्रेन’ का विषय नहीं है। प्रवासी पंजाबी राज्य की अर्थव्यवस्था में निवेश, कारोबार, शिक्षा और सामाजिक परियोजनाओं के माध्यम से योगदान भी कर सकते हैं। चुनौती यह है कि विदेश जाने वाले युवाओं को रोकने के बजाय पंजाब को ऐसा माहौल दिया जाए कि विदेश में अनुभव हासिल करने वाले युवा वापस लौटकर कारोबार, शोध और तकनीक के क्षेत्र में योगदान दें। इसके लिए नीति का फोकस रोजगार की संख्या के साथ उसकी गुणवत्ता, वेतन, कार्य वातावरण व करियर विकास पर होना जरूरी है।

असली कसौटी रोजगार की गुणवत्ता

पंजाब में युवाओं के विदेश जाने की समस्या का स्थायी समाधान केवल सरकारी भर्तियों की संख्या बढ़ाने से संभव नहीं होगा। सरकारी नौकरियां सीमित हैं, जबकि हर साल बड़ी संख्या में युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। इसलिए उद्योग, सेवा क्षेत्र, तकनीक, कृषि आधारित उद्यम और स्टार्टअप में बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करना जरूरी है। सरकार की मौजूदा पहलों का असर तभी दिखाई देगा, जब प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक आय वाले रोजगार मिलें।

नीति का अगला चरण

ब्रेन ड्रेन को रोकने की बहस अब ‘युवाओं को विदेश जाने से रोकने’ से आगे बढ़कर ‘पंजाब में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने’ पर केंद्रित हो रही है। रोजगार, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कई पहल शुरू की हैं, लेकिन इनके परिणामों का आकलन रोजगार पाने वाले युवाओं की संख्या, निजी क्षेत्र में वेतन और राज्य में टिके रहने वाले प्रतिभाशाली युवाओं के आधार पर करना होगा। यदि पंजाब में शिक्षा और रोजगार का ऐसा तंत्र तैयार होता है, जिसमें युवा अपनी योग्यता के अनुरूप करियर बना सकें, तो विदेश जाना उनकी मजबूरी के बजाय केवल एक विकल्प रह जाएगा।

हरियाणा में जेबीटी-सीएंडवी शिक्षकों को पदोन्नति का मौका, 13 अगस्त तक केस भेजने के निर्देश

शिक्षा विभाग ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम; पात्र शिक्षकों के पदोन्नति मामलों की जांच कर समय पर भेजने को कहा, सेवा रिकॉर्ड और पात्रता की जांच की जाएगी

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

हरियाणा में जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुल गया है।

शिक्षा विभाग ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को पात्र शिक्षकों के पदोन्नति मामलों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार कर

13 अगस्त तक भेजने के निर्देश दिए हैं। विभाग के इस कदम से लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

निर्देशों के तहत जिलों में संबंधित शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड और पात्रता की जांच की जाएगी। इसके बाद योग्य पाए जाने वाले शिक्षकों के

मामलों को निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। विभाग का जोर इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर है, ताकि पदोन्नति से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी न हो।

जेबीटी और सीएंडवी शिक्षक हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला कैडर के नियमित

शिक्षकों में शामिल हैं। राज्य की जिला कैडर नीति में जेबीटी, हेड टीचर और सीएंडवी शिक्षकों को जिला कैडर के तौर पर परिभाषित किया गया है।

ऐसे में पदोन्नति प्रक्रिया में संबंधित शिक्षकों की सेवा शर्तों, वरिष्ठता और निर्धारित पात्रता मानकों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा।

समयसीमा का पालन जरूरी

विभागीय निर्देशों के अनुसार डीईईओ को पात्र शिक्षकों के मामलों की आवश्यक जांच और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर 13 अगस्त तक केस भेजने होंगे। इससे संबंधित जिलों के अधिकारियों पर समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। शिक्षकों की ओर से उम्मीद की जा रही है कि इस प्रक्रिया के बाद पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।

शिक्षकों को राहत की उम्मीद

पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ने से जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों के करियर में अगला अवसर मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम पदोन्नति आदेश विभागीय जांच, पात्रता, वरिष्ठता और उपलब्ध पदों से जुड़े नियमों के अनुसार जारी होंगे। विभाग की ओर से पहले भी शिक्षकों से जुड़े सेवा मामलों और कैडर संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं।

सीईटी पास बेरोजगार युवाओं को मिलेगा मानदेय, हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं के रोजगार, कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी ने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) पास करने वाले ऐसे बेरोजगार युवाओं को, जिन्हें दो वर्ष तक रोजगार नहीं मिल पाएगा, 1 नवंबर से सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय प्रदान किया जाएगा।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग तथा हरियाणा कौशल विकास मिशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकों से



जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। सरकारों आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 5 लाख 40 हजार 428 सीईटी पास युवा इस योजना के दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत हरियाणा देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हुआ है और इस पहल के माध्यम से अब तक 51 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रदेश को उभरती तकनीकों का केंद्र बनाने की दिशा में सरकार पंचकूला और

गुरुग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हब स्थापित करेगी। इसके अलावा दो लाख युवाओं को हार्ड स्किल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्टीआई और कौशल विकास से संबंधित संपूर्ण डाटा एआई आधारित पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र

कलानौर: ट्रक से टक्कर में कार के उड़े परखच्चे तीन युवकों की मौके पर ही मौत

समर न्यूज़ | रोहतक

हरियाणा के रोहतक जिले में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की जान चली गई। यह हादसा कलानौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे-152डी पर खैरडी मोड़ के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

सुबह करीब 5:30 बजे एक टाटा कार अंबाला से नारनौल की ओर जा रही थी। इसी दौरान खैरडी मोड़ के निकट कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार आगे चल रहे ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। हादसे का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही कलानौर



थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने तीनों शवों को वाहन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों में एक की पहचान नारनौल की रामकरण दास कॉलोनी निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई है। जबकि अन्य दो युवकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी शिनाख्त के लिए प्रयास कर रही है और परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है। हादसे के बाद हाईवे

पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा और जाम जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

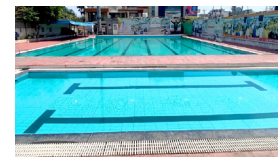
प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और ट्रक से पीछे से हुई टक्कर माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

16 महीने बाद फिर खुलेगा अंबाला कैट का ऑल वेदर स्विमिंग पूल, पहली अगस्त से मिलेगी सुविधा

समर न्यूज़ | अंबाला

लंबे इंतजार के बाद अंबाला छावनी के चार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम स्थित ऑल वेदर स्विमिंग पूल एक बार फिर तैराकों और आम नागरिकों के लिए खुलने जा रहा है। करीब 16 माह से बंद पड़ा यह स्विमिंग पूल 1 अगस्त से संचालन शुरू करेगा। खेल विभाग मुख्यालय ने जिला खेल विभाग को इसके संचालन की मंजूरी दे दी है, जिससे खिलाड़ियों और तैराकी सीखने के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

स्विमिंग पूल का संचालन प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 3 बजे से 8 बजे तक किया जाएगा। पूल शुरू होने से खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं आम नागरिकों को भी निजी स्विमिंग पूलों की तुलना में कम शुल्क पर तैराकी का अवसर



मिलेगा। दरअसल, मार्च 2025 में स्विमिंग पूल का पूर्व टेंडर समाप्त होने के बाद इसके संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। जिला खेल विभाग ने स्थानीय स्तर पर संचालन का प्रस्ताव तैयार कर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से मुख्यालय को भेजा था। हालांकि, अनुमति और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण मामला लंबे समय तक लंबित रहा।

इस दौरान खिलाड़ियों और तैराकों ने कई बार पूल शुरू करने की मांग उठाई। उनकी ओर से यह मुद्दा प्रदेश के मंत्री अनिल विज और खेल मंत्री गौरव गौतम के समक्ष भी रखा गया था। हालांकि आशवासन मिलने के बावजूद संचालन शुरू नहीं

हो सका। सितंबर 2025 में कुछ समय के लिए जिला खेल विभाग को संचालन की अनुमति मिली थी, लेकिन तब तक तैराकी का सीजन लगभग समाप्त हो चुका था।

अब खेल विभाग की मंजूरी मिलने के बाद जिला खेल विभाग स्वयं पूल का संचालन करेगा। इससे न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा, बल्कि अंबाला और आसपास के क्षेत्रों के तैराक भी नियमित अभ्यास कर सकेंगे।

उधर, शहाजदपुर के बड़ागढ़ स्थित आधुनिक खेल परिसर का मौसमी स्विमिंग पूल इस वर्ष भी आमजन के लिए शुरू नहीं किया जाएगा। ऐसे में अंबाला कैट का ऑल वेदर स्विमिंग पूल क्षेत्र के तैराकों के लिए प्रमुख विकल्प रहेगा। पूल के दोबारा शुरू होने से जिले में तैराकी खेल को बढ़ावा मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर मिलेगा।

ई-दिशा केंद्र का औचक निरीक्षण, डीसी ने सेवाओं और सुविधाओं का लिया जायजा

समर न्यूज़ | फतेहाबाद

आमजन को बेहतर, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने वीरवार को लघु सचिवालय स्थित ई-दिशा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध नागरिक सेवाओं, मूलभूत सुविधाओं और कार्यालय की

कार्यप्रणाली का गहनता से जायजा लेते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ई-दिशा केंद्र में स्थापित एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, प्रिंटर तथा अन्य तकनीकी उपकरणों की कार्यक्षमता की जांच की। कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

उम्मीद

ग्लासगो में शॉटपुट फाइनल में चौथे स्थान पर रहें

कॉमनवेल्थ: पदक से चूकीं अंबाला की मनप्रीत

समर न्यूज़ | अंबाला

ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के अंबाला की स्टार शॉटपुट खिलाड़ी मनप्रीत पदक जीतने से बेहद मामूली अंतर से चूक गईं। महिला गोला फेंक स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में मनप्रीत ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंतिम प्रयास में हुई तकनीकी चूक के कारण वह शीर्ष तीन में जगह नहीं बना सकीं और चौथे स्थान पर रहकर प्रतियोगिता समाप्त की।

देर रात हुए फाइनल मुकाबले में मनप्रीत ने आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की और शुरुआती प्रयासों में मजबूत चुनौती पेश की। दुनिया की 12 शीर्ष खिलाड़ियों के बीच हुए



कड़े मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी लगातार पदक की दौड़ में बनी रहें, लेकिन निर्णायक अंतिम थ्रो के दौरान गोले पर पकड़ पूरी तरह नहीं बन पाने से वह अपेक्षित दूरी हासिल नहीं कर सकीं। इसी वजह से उनका पदक जीतने का सपना अधूरा रह गया। इस बार प्रतियोगिता

के प्रारूप में बदलाव के चलते क्वालिफाईंग राउंड नहीं कराया गया और खिलाड़ियों को सीधे फाइनल में उतरना पड़ा। ऐसे में मुकाबला और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया था, जहां हर प्रयास का महत्व बढ़ गया था। अंबाला सिटी के जसमीत नगर की रहने वाली मनप्रीत भारतीय

एथलेटिक्स की अनुभवी शॉटपुट खिलाड़ी हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में इस खेल में अपना सफर शुरू किया था और लगातार मेहनत के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। अब तक वह 14 राष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं, जबकि दो बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करवा चुकी हैं।

वेटलिफ्टिंग पृष्ठभूमि से आने वाली मनप्रीत अपनी ताकत और तकनीक के लिए जानी जाती हैं। 145 किलोग्राम तक बेंच प्रेस करने की क्षमता रखने वाली यह खिलाड़ी भारतीय शॉटपुट की मजबूत दावेदारों में गिनी जाती है। ग्लासगो में यह उनका दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स था।

कैथल पुलिस का ‘ऑपरेशन हथियार’ सफल, 5 मामलों में 6 आरोपी गिरफ्तार

चार देसी कट्टे, दो पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद



बलिनंदर कुमार | कैथल समर न्यूज़

जिले में अपराध और अवैध हथियारों के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए कैथल पुलिस ने तीन दिवसीय विशेष अभियान ‘ऑपरेशन हथियार’ के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। अभियान के दौरान पुलिस ने अलग-अलग पांच मामलों में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चार देसी कट्टे, दो पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का मानना है कि ये आरोपी अवैध हथियारों के सहारे किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकते थे, लेकिन समय रहते कार्रवाई कर संभावित घटनाओं को टाल दिया गया।

डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत जिलेभर में सघन जांच और छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि जुलाई माह के दौरान ही कैथल पुलिस 12 मामलों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर 13 अवैध हथियार और 9 कारतूस

बरामद कर चुकी है। पहले मामले में एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव मोहना के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-152डी पर दबिश देकर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांव नैथला निवासी रविंद्र को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से .315 बोर का एक अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना पूंडरी में मामला दर्ज किया गया है।

दूसरे मामले में एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ ने गांव किठाना की अनाज मंडी स्थित एक कमरे में छापेमारी कर सुनील उर्फ शीली को गिरफ्तार किया। उसके पास से .315 बोर का अवैध कट्टा बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि हथियार उसे कननाल निवासी लवी ने उपलब्ध कराया था। पुलिस ने तत्परात दिखाते हुए लवी को भी गिरफ्तार कर लिया।

तीसरे मामले में सीआईएफ-1 की टीम ने ढांड रोड स्थित हांसी-बुटाना नहर पुल के पास से जींद जिले के साहिल उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भी .315 बोर का अवैध कट्टा बरामद हुआ।

धारूहेड़ा में गैस रिफिलिंग के दौरान भीषण विस्फोट, चार झुलसे; दो की हालत गंभीर

समर न्यूज़ | रेवाड़ी/धारूहेड़ा

धारूहेड़ा की ओम नगर कॉलोनी में शाम गैस रिफिलिंग के दौरान हुए जोरदार विस्फोट से चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायलों में दो की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

कॉलोनी स्थित एक दुकान पर बड़े एलपीजी सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी। इसी दौरान गैस रिसाव होने से अचानक विस्फोट हो गया और आग भड़क उठी। आग की चोट में आने से वहां मौजूद चार लोग बुरी तरह झुलस गए। घायलों की पहचान बिहार के



वैशाली जिले के रहने वाले अभय कुमार, विनय, चंदन और पिंटू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि चारों धारूहेड़ा में निवास करते हैं, जिन्हें बेहतर निजी कंपनियों में कार्यरत हैं। घटना के समय वे दुकान पर मौजूद थे, तभी यह हादसा हो गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव के कारण हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ब्यास-चिनाब लिंक परियोजना का निर्माण करेगी एनएचपीसी

चिनाब को ब्यास नदी से जोड़ने पर आयेगी 2354 करोड़ रुपए की लागत, 10 अगस्त तक ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किए

संजु | शिमला
समर न्यूज

ऊर्जा सेक्टर में नई ऊंचाइयां छूने वाली देश की नवरत्न कंपनी एनएचपीसी हिमाचल में एक और प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है। 2354 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ब्यास-चिनाब लिंक परियोजना हेतु एनएचपीसी ने दस्तावेजों और तकनीकी प्रक्रियाओं को गति देते हुए 10 अगस्त तक ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किए हैं।

एनएचपीसी के कॉरपोरेट ऑफिस फरीदाबाद से मिली जानकारी के मुताबिक ऊर्जा कंपनी एनएचपीसी को भारत सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण ‘नदी जोड़ो प्रोजेक्ट’ का निर्माण कार्य सौंपा है। इसके लिए विभिन्न निर्माण एजेंसियों से सविधा मांगी जा रही है। बताया जा रहा है कि एनएचपीसी के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं, जिस कारण केंद्र सरकार ने देश हित की इस प्रोजेक्ट को ऊर्जा कंपनी को सौंपा है, जबकि पार्वती प्रोजेक्ट में बनाई गई एशिया की सबसे लंबी 32

सांसद सुरेश कश्यप ने उठाया एससी छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ा मुद्दा

निधि आवंटन की जानकारी मांगी, केंद्र सरकार ने साझा किए लाभार्थियों के आंकड़े

सोलन : शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति को लेकर प्रश्न उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से देश, हिमाचल प्रदेश और शिमला संसदीय क्षेत्र में इन योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत छात्रवृत्तियों, लाभार्थियों की संख्या और निधि आवंटन से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी।

लोकसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने उत्तर देते हुए बताया कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल रही है।मंत्री ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में केंद्र और राज्यों के बीच सामान्यतः



60:40 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी होती है, जबकि हिमाचल प्रदेश सहित कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 90:10 का प्रावधान लागू है। उन्होंने कहा कि आवेदन, सत्यापन और स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, शिमला जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच हर वर्ष हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिला। इसी अवधि में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों तक छात्रवृत्ति का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन योजनाओं से भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश, विशेषकर शिमला संसदीय क्षेत्र के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलता रहेगा।

धर्मशाला डिपो को मिली पांच नई हाईटेक इलेक्ट्रिक बसें

विभिन्न रूटों पर यात्रियों को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यात्रा का मिलेगा लाभ

राहुल | धर्मशाला
समर न्यूज

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के धर्मशाला डिपो के बेड़े में पांच नई अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो गई हैं। मुख्यालय से अंतिम स्वीकृति और संचालन संबंधी निर्देश मिलने के बाद इन बसों को विभिन्न रूटों पर चलाया जाएगा। नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने बताया कि इस बार निगम ने ओलेक्ट्रा कंपनी की आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल किया है। इससे पहले धर्मशाला डिपो में पीएमआई कंपनी की इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही थीं। नई बसों में 32



यात्रियों के बैठने की क्षमता है और इन्हें नवीनतम तकनीक तथा बेहतर सुरक्षा सुविधाओं से लैस किया गया है।उन्होंने बताया कि नई बसों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अधिक दूरी तय करने की क्षमता है। पहले संचालित इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज होने पर लगभग 150 किलोमीटर तक चलती थीं, जबकि

नई बसें एक बार चार्ज में करीब 180 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगी। इसके अलावा इन बसों में बेहतर सर्विसेशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे पहाड़ी मार्गों पर भी यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही ये बसें कम शोर करती हैं और पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल हैं।

धर्मशाला-त्रियुंड ट्रैक पर बढ़ेगी सुविधाएं, सुरक्षा भी होगी मजबूत

30 लाख रुपये से होंगे विकास कार्य, पेयजल सुविधा में होगा सुधार

राहुल | धर्मशाला
समर न्यूज

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन एवं ट्रैकिंग स्थल त्रियुंड ट्रैक पर आने वाले पर्यटकों और ट्रेकर्स को जल्द बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

वन विभाग ने ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की योजना तैयार की है। इसके तहत लगभग 30 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे, जबकि पेयजल सुविधा को भी बेहतर बनाया जाएगा। धर्मशाला वन मंडल के डीएफओ अमित शर्मा ने बताया कि त्रियुंड धौलाधार लैंडस्केप का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और इको-टूरिज्म गतिविधियों के लिए देश-विदेश के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है।

उन्होंने कहा कि यह एक संरक्षित वन क्षेत्र है, इसलिए यहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए सीमित स्तर पर ही किया जाएगा,



स्टेट इको-टूरिज्म सोसायटी ने दिया 15 लाख का लोन

इस परियोजना के लिए 15 लाख का ऋण स्टेट इको-टूरिज्म सोसायटी से प्राप्त हो चुका है, जबकि शेष धनराशि के लिए जिला प्रशासन से सहयोग का आश्वासन मिला है। विभाग का कहना है कि मानसून समाप्त होने के बाद विकास कार्यों को गति दी जाएगी, जिससे आने वाले पर्यटन सीजन में ट्रैक पर पहुंचने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

ताकि क्षेत्र की प्राकृतिक पहचान और जैव विविधता सुरक्षित रह सके। त्रियुंड ट्रैक एक एडवेंचर गतिविधि है, इसलिए केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम लोगों को ही इस ट्रैक पर जाना चाहिए। पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वन विभाग ने ट्रैक पर वायरलेस संचार प्रणाली शुरू कर दी है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क स्थापित किया जा सके। इसके

अलावा त्रियुंड और करेरी में पांच-पांच स्ट्रेचर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी समस्या की स्थिति में घायल ट्रेकर्स का शीघ्र रेस्क्यू किया जा सके।वन विभाग के अनुसार इस वर्ष ट्रैक पर गजबो, रेन शेल्टर और आकर्षक प्रवेश द्वार जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। साथ ही लाका से त्रियुंड तक पेयजल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना भी तैयार की गई है।

नशा तस्करी के अपराधियों पर सख्ती बरत रही पुलिस

राहुल | धर्मशाला
समर न्यूज

जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अपना अभियान और तेज कर दिया है। चिट्ठा, हेरोइन और चरस जैसे नशीले पदार्थों की अवैध सप्लाई पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही बार-बार नशा तस्करी के मामलों में पकड़े जाने वाले आरोपियों के खिलाफ अब कानूनी स्तर पर भी सख्त रणनीति अपनाई जा रही है।

पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि नशा तस्करी का नेटवर्क बेहद संगठित होता है, जिसे तोड़ना आसान नहीं है। तस्करों तक पहुंचने के लिए पुलिस को मजबूत खुफिया तंत्र, लगातार निगरानी और तकनीकी संसाधनों का सहारा लेना



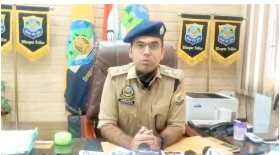
पड़ता है। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है और अभियान के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एसपी ने बताया कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अपने मुखबिर तंत्र को और मजबूत कर रही है ताकि तस्करी की हर गतिविधि पर समय रहते नजर रखी जा सके। इसके अलावा सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है।

बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमृतसर से चिट्ठा सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार

सुभाष | बिलासपुर
समर न्यूज

हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने चिट्ठा तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर के एक कार्रवाई सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 12.5 ग्राम चिट्ठा, एक अवैध पिस्तौल और सात जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 27 जुलाई को आरटीओ बैरियर पर नाकाबंदी के दौरान दिल्ली से लेह जा रही एचआरटीसी बस



की तलाशी ली गई थी। इस दौरान तीन यात्रियों के कब्जे से 27.60 ग्राम चिट्ठा (हेरोइन) बरामद हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी सुनील और अनिल राठी तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू निवासी नीरत सिंह के रूप में हुई। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने मामले की सप्लाई चेन की पड़ताल की, जिसमें

पता चला कि बरामद चिट्ठा अमृतसर निवासी विजय कुमार से खरीदा गया था। इसके बाद बिलासपुर पुलिस की टीम ने अमृतसर में दबिशा देकर 29 जुलाई को विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 12.5 ग्राम चिट्ठा, एक अवैध पिस्तौल और सात जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बरामद हथियार और मादक पदार्थ के संबंध में नियमानुसार अलग से कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि विजय कुमार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश और पंजाब में चिट्ठा तस्करी से जुड़े पांच अपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।

समर न्यूज | शिमला

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को कांग्रेस सरकार की नीतियों पर बड़ा सवाल बताया।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय साबित करता है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करते हुए ऐसे प्रावधान लागू किए, जो न्यायिक कसौटी पर टिक नहीं सके। जब सरकार ने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में संशोधन का विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया था, तब भाजपा ने इसका विरोध करते हुए



स्पष्ट कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट अवधि को वरिष्ठता और वित्तीय लाभों से अलग रखना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। भाजपा ने उस समय भी चेताया था कि ऐसा कानून अदालत में टिकना मुश्किल होगा और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उस आशंका को सही साबित कर दिया है। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मामलों को लेकर गंभीर नहीं है।

बढ़ले की राजनीति से न मुख्यमंत्री, न प्रदेश और न ही अधिकारियों का भला होगा: जयराम ठाकुर

समर न्यूज | शिमला

मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रतिशोध की जिस राह पर चल रहे हैं, उससे किसी का लाभ नहीं होने वाला। अपनी नاکामी को छिपाने और निजी शत्रुता निकालने के लिए जिस तरह से वह बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।

जब से राज्यसभा चुनाव में बहुमत होने के बावजूद वह हारे हैं, तब से वह अधिकारियों के जरिए बीजेपी नेताओं को परेशान करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। विजिलेंस के जरिए सभी



के खिलाफ साजिशान कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले मार्च में उन्होंने विजिलेंस को आरटीआई के दायरे से बाहर किया, इसके बाद फैब्रिकेटेड शिकायतें करके लोगों को फंसाने का काम चल रहा है। जो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ सिर उठा रहे

एक बड़े मंत्री के खिलाफ भी सीएम ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। वह मंत्री आलाक़मान तक गए, फिर वह जांच ठंडे बस्ते में चली गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी तरह मुख्यमंत्री भाजपा नेताओं के साथ विजिलेंस जांच के नाम पर अपनी खुरस निकाल रहे हैं।

वह भूल रहे हैं कि भाजपा को वह डरा नहीं सकते हैं। उनके खिलाफ एक के बाद एक आरोप लगे। उनके ही पार्टी के उपाध्यक्ष ने अटैचियां इकट्ठा करने का आरोप लगाया। लेकिन मुख्यमंत्री ने उन अटैचियों की जांच नहीं करवाई। पूरी संभावना है कि आरोप लगाने वालों पर ही जांच बैठा दी जाए।

सरदार पटेल विवि में अब तक 50% से अधिक बीएड सीटें भरी

धर्मवीर | मंडी
समर न्यूज

सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए बीएड के पहले चरण की काउंसिलिंग शुरू हो चुकी है। 27 जुलाई से शुरू हुई यह प्रक्रिया कल यानी 31 अगस्त तक जारी रहेगी। बता दें कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अधीन मंडी और कुल्लू जिलों के 12 बीएड कॉलेज आते हैं जिनकी 1350 सीटों के लिए यह काउंसिलिंग प्रक्रिया चली हुई है।

यूनिवर्सिटी के वायस चांसलर प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में ऑफलाइन काउंसिलिंग में 53 से अधिक अंक लेने वाले पात्र अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट, आरक्षण नीति एवं यूनिवर्सिटी के प्रचलित नियमों



के अनुसार पारदर्शी तरीके से संग्रह करवाई जा रही है। वायस चांसलर ने बताया कि अभी तक 50 प्रतिशत से अधिक सीटें भरी जा चुकी हैं और पहले चरण में ही अधिकतर सीटें भरे जाने की पूरी संभावना है। जो सीटें रह जाएंगी उन्हें दूसरे-तीसरे चरणों में नियमों के तहत ही भरा जाएगा।

उन्होंने विद्यार्थियों व अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना अथवा अनधिकृत स्रोतों पर विश्वास न करें। प्रवेश संबंधी सभी जानकारी केवल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम एवं अधिसूचनाओं के आधार पर ही मान्य होगी।

सौगात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को हरित और आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई

हिमाचल की जनता को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात!

■ आरडीजी बंद होने को लेकर बीजेपी पर बरसे सीएम सुक्खू
संजु | सोलन
समर न्यूज

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के क्यारीघाट में प्रदेशवासियों को ‘हिम-बस प्लस स्मार्ट ट्रैवल कार्ड’ और नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को हरित और आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार के व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों से भाजपा बौखला गई है। सोलन जिले के क्यारीघाट के होटल मेघदूत में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ‘हिम-बस



प्लस स्मार्ट ट्रैवल कार्ड’ लॉन्च किया और नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ आधुनिक और सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और व्यवस्था परिवर्तन के लिए

लगातार फैसले ले रही है, जिससे भाजपा बौखला गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) बंद करवाने की पैरवी कर प्रदेश के हितों को नुकसान पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय भाजपा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर सवाल उठाती थी, लेकिन आज हिमाचल के पास

500 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा तैयार है। उन्होंने बताया कि 297 नई इलेक्ट्रिक बसें विभिन्न डिपो में भेजी जा चुकी हैं। इन बसों के संचालन से प्रति किलोमीटर 40 से 50 रुपये तक की बचत हो रही है, जिससे एचआरटीसी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने और 2030 तक प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के व्यापक आधुनिकीकरण का लक्ष्य तय किया है। इसी दिशा में इस वर्ष 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और भविष्य में 100 हाइड्रोजन बसें भी चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि नई इलेक्ट्रिक बसें अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और एक बार चार्ज होने पर लगभग 180 किलोमीटर तक चल सकती हैं।

सुभाष | बिलासपुर
समर न्यूज

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बढ़ते नशे के कारोबार, बेरोजगारी, जर्जर सड़कों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रहित और जनहित से जुड़े मुद्दों पर जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।

बिलासपुर के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विशाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अव्यवस्था का माहौल है, जो सरकार की नीतियों



। कानून व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति फैल रही है और रोजगार के पर्याप्त अवसर न मिलने से युवा निराश हैं। विशाल ठाकुर ने बताया कि 25 और 26 जुलाई को उनामें एबीवीपी की दो दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी बैठक सफलतापूर्वक आयोजित हुई। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

मोटर दुर्घटना मामलों में उचित मुआवजा वास्तविक आर्थिक नुकसान के अनुरूप होना चाहिए : हाई कोर्ट

ट्रिब्यूनल की गणना में त्रुटि सुधारते हुए कारोबारी के परिवार को 13.13 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा

मोनिका रावत | चंडीगढ़
समर न्यूज़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मोटर दुर्घटना मामलों में दिया जाने वाला उचित मुआवजा (जस्ट कंपेंसेशन) ऐसा होना चाहिए जो मृतक के आश्रितों को हुई वास्तविक आर्थिक क्षति का निपक्ष और न्यायसंगत प्रतिबिंब हो। अदालत ने कहा कि मुआवजा न तो ऐसा होना चाहिए जिससे दावेदारों को अनुचित लाभ मिले और न ही इतना कम कि कानून का कल्याणकारी उद्देश्य ही विफल हो जाए।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी वर्ष 2015 की सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक कारोबारी के परिवार की अपील स्वीकार करते हुए की। हाई कोर्ट ने पाया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी), चंडीगढ़



ने मुआवजे की गणना करते समय भविष्य की आय वृद्धि (फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स) को शामिल नहीं किया और व्यक्तिगत खर्चों की कटौती भी गलत आधार पर की। इसके चलते अदालत ने परिवार को दिए गए मुआवजे में 13.13 लाख रुपये की वृद्धि कर दी।

मामला कारोबारी की पत्नी, दो बच्चों और मां द्वारा दायर अपील से जुड़ा था। कारोबारी 31 जनवरी 2015 को मानसा से चंडीगढ़ जा रहे थे, तभी सड़क दुर्घटना में उनकी

मृत्यु हो गई थी। एमएसीटी ने परिवार को 38.35 लाख रुपये का मुआवजा दिया था, लेकिन आश्रितों ने केवल मुआवजे की राशि को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना के लिए लापरवाही, वाहन के बीमा रहित होने तथा चालक और मालिक की संयुक्त एवं पृथक देयता संबंधी ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों से जुड़ा था। कारोबारी 31 जनवरी 2015 को मानसा से चंडीगढ़ जा रहे थे, तभी सड़क दुर्घटना में उनकी

हुए अदालत ने माना कि ट्रिब्यूनल ने आयकर रिटर्न के आधार पर मृतक की वार्षिक आय 3,97,500 रुपये सही निर्धारित की थी, लेकिन 45 वार्षिक स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति होने के कारण उसमें 25 प्रतिशत फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जोड़ना आवश्यक था। इससे वार्षिक आय 4,96,875 रुपये हो गई।

अदालत ने यह भी माना कि आश्रितों की निर्भरता की गणना से पहले आयकर की देय राशि घटाई जानी चाहिए। जस्टिस गुप्ता ने कहा, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का उद्देश्य आश्रितों को कमाने वाले सदस्य की मृत्यु से हुए वास्तविक आर्थिक नुकसान की भरपाई करना है। इसलिए आय के उस हिस्से के आधार पर मुआवजे की गणना नहीं की जा सकती, जिसे मृतक कानूनन आयकर के रूप में राज्य को देने के लिए बाध्य था।

आयकर के 24,687 रुपये घटाने के बाद अदालत ने निर्भरता की गणना के लिए शुद्ध वार्षिक आय 4,72,188 रुपये मानी। इसके बाद हाई कोर्ट ने पाया कि चार आश्रित होने के बावजूद ट्रिब्यूनल ने व्यक्तिगत खर्च के रूप में एक-तिहाई आय घटा दी थी, जबकि कानून के अनुसार एक-चौथाई कटौती ही उचित थी। इस आधार पर परिवार के लिए वार्षिक आर्थिक योगदान 3,54,141 रुपये पुनर्निर्धारित किया गया।

पारंपरिक मंदों के तहत भी मुआवजे में संशोधन करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया, अपीलकर्ता-दावेदारों को ट्रिब्यूनल द्वारा पहले से दिए गए मुआवजे के अतिरिक्त 13,13,000 रुपये का बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाता है। यह राशि दावा याचिका दायर किए जाने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देय होगी।

‘मेरा वार्ड, मेरा परिवार’: जसमनप्रीत सिंह ने गिनाई उपलब्धियां, अधूरे कामों पर भी रखी बात

क्रिकेटर बनने का था सपना, 19 वर्ष की उम्र में शुरू हुआ राजनीतिक सफर



शगुन कश्यप। चंडीगढ़
समर न्यूज़



‘मेरा वार्ड, मेरा परिवार’ विशेष शृंखला में चंडीगढ़ के वरिष्ठ उपमहापौर और वार्ड नंबर-32 के पार्षद जसमनप्रीत सिंह ने अपने राजनीतिक सफर, वार्ड में कराए गए विकास कार्यों और आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर खुलकर बात की।

उन्होंने दावा किया कि अपने कार्यकाल में सड़कों, जलभराव, स।मु.दा.ि.य.क. सुविधाओं और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी गई। जसमनप्रीत सिंह ने बताया कि बचपन में उनकी राजनीति में आने की कोई योजना नहीं थी। वह क्रिकेटर बनना चाहते थे और आज भी क्रिकेट को अपना पहला प्यार मानते हैं। उनके अनुसार, एक



मित्र के माध्यम से वह राजनीति से जुड़े और करीब 19 वर्ष की उम्र से संगठन में काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में मिले सम्मान, अवसर और कार्यकर्ताओं के सहयोग के कारण उन्होंने लगातार सक्रिय रहकर अपनी राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ाई।

प्रमुख दावे

- वार्ड की लगभग 80 प्रतिशत सड़कों की कारपेटिंग
- सेक्टर-44 में जल निकासी व्यवस्था में सुधार
- सेक्टर-51 में सामुदायिक केंद्र और डिस्पेंसरी मंजूर
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए संपर्क केंद्र शुरू

पांच वर्ष तक जनता के बीच सक्रिय रहने का दावा
आगामी चुनाव पर उन्होंने कहा कि टिकट और जीत का अंतिम फैसला पार्टी तथा जनता करेगी। उन्होंने वार्डवासियों से पहले जैसा समर्थन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि का काम केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे कार्यकाल में लोगों के बीच रहना है।

■ सड़कों और जलभराव को बताया प्राथमिक मुद्दा
वार्ड में कराए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र की करीब 80 प्रतिशत सड़कों की कारपेटिंग कराई जा चुकी है। शेष सड़कों का काम मानसून के बाद पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सेक्टर-44 में जलभराव की समस्या को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर पाइपलाइन डनवाई गई और रैट गिलियों का निर्माण कराया गया। उनका दावा है कि इन उपायों के बाद इस मानसून में क्षेत्र में पहले जैसी गंभीर जलभराव की स्थिति सामने नहीं आई। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सभी समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं और कुछ काम अभी बाकी हैं। ऐसे में सड़कों और जल निकासी को लेकर किए गए दावों की वास्तविक स्थिति का आकलन स्थानीय निवासियों के अनुभव और आगामी बरसात में ही स्पष्ट होगा।

सेक्टर-51 में सामुदायिक केंद्र और डिस्पेंसरी का प्रस्ताव
जसमनप्रीत सिंह ने बताया कि सेक्टर-51 में सरकारी सुविधाओं के लिए भूमि उपलब्ध न होने की समस्या लंबे समय से थी। उनके अनुसार, क्षेत्र में करीब द्वाइ एकड़ भूमि पर सामुदायिक केंद्र और आधा एकड़ भूमि पर डिस्पेंसरी के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई गई है। उन्होंने इन परियोजनाओं को अपने कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, लेकिन इनका निर्माण पूरा होना अभी बाकी है। ट.र-44 में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए सामुदायिक केंद्र के एक स्टोर रूम को संपर्क केंद्र में बदलने का भी दावा किया गया। इससे लोगों को बिल जमा कराने और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए दूसरे सेक्टरों में नहीं जाना पड़ रहा।

मोहाली में बसों के कारण सड़क पर लग रहे जाम से हादसों को न्योता

फेज-6 बस स्टैंड के बाहर से सवारियां उठा रहे बस ऑपरेटर

■ सड़क पर खड़ी बसों की भी पचीं कोटने का आरोप, बस स्टैंड प्रभारी ने किया इन्कार
निशान | मोहाली
समर न्यूज़

मोहाली के फेज-6 बस स्टैंड के बाहर यातायात नियमों की कथित रूप से लगातार अनेदेखी हो रही है। बसों द्वारा मुख्य सड़क पर ही यात्रियों को चढ़ाने और उतारने का सिलसिला जारी रहने से रोजाना लंबा यातायात जाम लग रहा है। इससे आम लोगों को परेशानी होने के साथ सड़क हादसों का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय लोगों और राहगीरों का कहना है कि सड़क के बीच बसें रुकने से अन्य वाहनों



की आवाजही प्रभावित होती है। कार्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों की ओर जाने वाले लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को भी रास्ता बनाने में कठिनाई होती है। मामलों में यह आरोप भी सामने आया है कि बस स्टैंड के बाहर सड़क किनारे बसों की 124 रुपये की पचीं काटी जा रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह प्रक्रिया काफी समय से चल रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।



इस संबंध में फेज-6 बस स्टैंड के प्रभारी सुखविंदर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बस स्टैंड के बाहर किसी प्रकार की पचीं नहीं काटी जाती। हालांकि, मौके पर मौजूद समाचार टीम ने सड़क किनारे पचीं काटे जाने का दावा किया। इससे बस स्टैंड प्रभारी के बयान और मौके की स्थिति के बीच विरोधाभास

चंडीगढ़ में 358 घरों का बिजली बिल शून्य, सौर ऊर्जा से बढ़ी बचत

शहर में 1,368 घरों पर लगे रूफटॉप सोलर सिस्टम, अधिक क्षमता वाले सिस्टम भी दिलचस्पी

■ अधिक क्षमता वाले संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा फायदा, ऋण लेने में कम रुचि
समर न्यूज़। चंडीगढ़

चंडीगढ़ में रूफटॉप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले कई घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल से राहत मिलने लगी है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, शहर में 1,368 घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

इनमें से 358 घर ऐसे हैं, जहां सौर ऊर्जा से बिजली की जरूरत पूरी होने के बाद बिजली बिल शून्य तक पहुंच गया है। इससे सौर ऊर्जा को लेकर शहर में लोगों की बढ़ती रुचि का पता चलता है। सौर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं में अधिक

सब्सिडी से घटता खर्च
रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने में केंद्र की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को सौर संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता मिलती है। संयंत्र की क्षमता के आधार पर सब्सिडी का लाभ मिलता है, जिससे शुरुआती निवेश का बोझ कम होता है। हालांकि, वास्तविक बिजली बिल शून्य होना घर की खपत, संयंत्र की क्षमता, मौसम और ग्रिड को भेजी गई बिजली की गणना पर निर्भर करता है।

ऋण में कम रुचि
सौर संयंत्र लगाने के लिए बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद कई उपभोक्ता कर्ज लेने से बच रहे हैं। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि कुछ परिवार अपनी बचत से संयंत्र लगाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग ऋण की मासिक किस्त और ब्याज को लेकर सहज नहीं हैं। ऐसे में सब्सिडी के साथ आसान वित्तीय व्यवस्था सौर ऊर्जा को तेजी से अपनाने में मदद कर सकती है।

बिजली बचत के साथ पर्यावरण लाभ
रूफटॉप सोलर का लाभ केवल बिजली बिल कम होने तक सीमित नहीं है। इससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटती है और स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ता है। चंडीगढ़ जैसे शहर में बढ़ी संख्या में घरों की छतों पर सौर संयंत्र लगाने से भविष्य में बिजली की मांग के दबाव को कम करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए उपभोक्ताओं को सही क्षमता का संयंत्र चुनने और स्थापना के बाद नियमित रखरखाव पर भी ध्यान देना होगा।

क्षमता वाले सिस्टम को लेकर भी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। खासकर 3 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले संयंत्र उन परिवारों के लिए उपयोगी

साबित हो रहे हैं, जिनकी बिजली खपत अपेक्षाकृत ज्यादा है। ऐसे घरों में सौर ऊर्जा से दिन के समय बिजली की जरूरत पूरी करने के

साथ अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजने का विकल्प भी उपलब्ध होता है। इससे बिजली की कुल खपत और बिल पर असर पड़ता है।

स्टूडेंट्स का टैलेंट बढ़ाना पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी : केपी शर्मा

गुरमीत सिंह | डेराबस्सी
समर न्यूज़

लायंस क्लब डेराबस्सी ने लोकल ग्लोबल विज्डम स्कूल में “स्टूडेंट्स के सामने आने वाली चुनौतियां और समाधान” विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। इस इवेंट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी जानी-मानी हस्तियां, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स और बच्ची संख्या में स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और अपने विचार शेयर किए।

लॉयंस क्लब डेराबस्सी के प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड मोहाली के पूर्व चेयरमैन केपी शर्मा ने कहा कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में सुधार सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज के स्टूडेंट्स और युवा कल के देश और समाज की जिम्मेदारी कंधों पर धरे हैं। इसलिए एजुकेशन जैसे सेंसिटिव सबजेक्ट को पॉलिटिकल इंटरैस्ट के बजाय समाज के भविष्य से जोड़कर देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत



है उसे पहचानने, उसे निखारने और सही गाइडेंस देने की। यह जिम्मेदारी सिर्फ टीचर या पेरेंट्स की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। स्कूल चेयरमैन गुरदीप सिंह चहल ने अपने भाषण में कहा कि स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान देने का सेंटर नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनेलिटी डेवलपमेंट का भी एक मॉड्यम है।

लॉयंस क्लब सेक्रेटरी उपेशा बंसल, स्कूल प्रिंसिपल लायन डॉ. बरखा राम और दूसरे वक्ताओं ने भी स्टूडेंट्स को समय की कीमत, डिसिप्लिन, मोरल वैल्यूज, डिजिटल एज की चुनौतियों, ड्रग्स से दूर रहने और अपनी जिंदगी में एक क्लियर गोल सेट करके उसे कड़ी मेहनत से हासिल करने के लिए मोटिवेट किया। स्टूडेंट्स ने भी खुलकर अपने विचार साझा किए।

दावा

फेज-7 में झूले, पार्क लाइटें, खुले व्यायाम स्थल और खेल सुविधाएं विकसित कराने का दावा

वार्ड-12 में पार्क, सीवरेज और जल निकासी पर विशेष जोर: पार्षद अनुराधा आनंद

■ पार्षद ने कहा-शहर का दायरा बढ़ा, लेकिन सीवरेज सफाई के संसाधन उसी अनुपात में नहीं बढ़े
सुरिंदर सिंह अंकुश/निशान सिंह
मोहाली। समर न्यूज़

वार्ड नंबर-12, फेज-7 की पार्षद अनुराधा आनंद ने अपने क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों और भविष्य की प्राथमिकताओं का ब्योरा देते हुए कहा कि पाकों के सौंदर्यीकरण, सीवरेज व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, बरसाती पानी की निकासी और जनसुविधाओं में सुधार पर लगातार काम किया जा रहा है।

वह पिछले कार्यकाल में नगर निगम की सदस्य भी रह चुकी हैं। वार्ड के अलग-अलग पाकों में बच्चों के लिए नए झूले लगाए गए हैं और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। पांच से छह पाकों में खुले व्यायाम स्थल विकसित किए गए हैं।

इसके अलावा अलग-अलग पाकों में मौसम से बचाव के लिए आश्रय स्थल, बैडमिंटन कोर्ट और एक वॉलीबॉल कोर्ट तैयार करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाकों को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। अनुराधा आनंद ने बताया कि वार्ड में वर्षों पुरानी सीवरेज पाइपलाइन को बदलवाना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल रहा।

उनके अनुसार, कुछ स्थानों पर करीब 50 से 60 वर्ष पुरानी पाइपलाइन के कारण बार-बार समस्या उत्पन्न होती थी। नई पाइपलाइन डालने से कई क्षेत्रों में सीवरेज संबंधी शिकायतों में कमी आई है। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए भी नई पाइपलाइन बिछाई गई। बरसाती पानी की निकासी से जुड़े मुद्दों को समय-समय पर नगर निगम और संबंधित विभागों के समक्ष उठाया गया। उन्होंने बताया कि वार्ड में गलियों की पहचान आसान बनाने के लिए आकर्षक नंबर प्लेटें लगाई गई हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए गए और लोगों को पौधारोपण तथा

स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया गया। कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों के लिए दवाइयां, सब्जियां और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध

पार्षद का ड्रीम प्रोजेक्ट
अनुराधा आनंद ने बताया कि वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रमुख स्थानों पर निगरानी कैमरे लगवाना उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा कमरा या बैठक स्थल बनवाने की योजना है, जहां वे बैठ सकें, आपस में संवाद कर सकें और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकें।

कराने के लिए शिविर लगाए गए। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से मोहाली शहर में राशन भी वितरित किया गया और संक्रमण से बचाव के लिए सफाई एवं संक्रमणरोधी छिड़काव करवाया गया।

ईरान-अमेरिका टकराव का दायरा बढ़ा पहली बार मिस्र तक पहुंची जंग की आंच

दमियाता बंदरगाह पर ड्रोन हमले से दो गैस जहाजों में आग, ट्रंप की चेतावनी के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा

एजेंसी। वॉशिंगटन/तेहरान/काहिरा

ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य टकराव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। पहली बार इस संघर्ष की आंच मिस्र तक पहुंची, जहां दमियाता बंदरगाह पर ड्रोन हमले में दो गैस से लदे जहाजों में आग लग गई। मिस्र सरकार ने शुरुआती जांच के बाद स्पष्ट किया कि यह हादसा नहीं बल्कि ड्रोन हमला था।

हालांकि किसी संगठन का आधिकारिक दावा सामने नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी और पश्चिमी मीडिया रिपोर्टों में ईरान समर्थित तत्वों पर संदेह बताया गया है। इस घटना के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता और बढ़ गई है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी कंपनी



के प्राकृतिक गैस भंडारण पोत एनरगोस विंटर को निशाना बनाया गया, जिसके बाद आग पास में मौजूद गैसलोंग सलेम जहाज तक फैल गई। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया कि हमले का उद्देश्य यह संदेश देना था

कि यदि संघर्ष और बढ़ा तो वैश्विक समुद्री व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हालात और बिगड़े तो अमेरिका पहले से भी अधिक व्यापक सैन्य कार्रवाई करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि ईरान

तैयार हो तो कूटनीतिक समाधान के रास्ते अब भी खुले हैं। दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रिवालयुशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि अमेरिका को उसकी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। ईरान ने यह भी दोहराया कि होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में उसकी सैन्य मौजूदगी मजबूत है और क्षेत्रीय सुरक्षा उसके नियंत्रण में है। इसी दौरान इराक में ईरान समर्थित

पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ठिकानों पर अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त कार्रवाई में कम से कम 20 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। जॉर्डन ने गुरुवार तड़के ईरान की ओर से दागी गई पांच मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की जानकारी दी। वहीं इजराइल ने दक्षिणी सीरिया के कुनेत्रा क्षेत्र में गोलाबारी की, जबकि कुवैत में एक चीनी कंपनी

की इमारत पर मिसाइल गिरने से एक कर्मचारी की मौत हो गई।

कूटनीतिक हल की कोशिशें जारी: तनाव के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान से वार्ता फिर शुरू करने की अपील की है। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान, कतर या किसी अन्य देश में अमेरिका के साथ नई बातचीत की खबरों को खारिज कर दिया।

भारतीयों पर भी असर: तनाव का असर वैश्विक बाजार पर दिखने लगा है। ब्रेंट कच्चा तेल 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, कीमत 100 डॉलर तक जा सकती है। इस बीच, भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में बंद हुए एक ईरानी अस्पताल से प्रभावित 130 से अधिक भारतीयों को हरसंभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है।

भारतीय नौसेना के लिए सातवां एएसडब्ल्यू शैलो वॉटरक्राफ्ट ‘अभय’ लॉन्च, मजबूत होगी सुरक्षा

करीब 77 मीटर लंबा पोत तटीय जलक्षेत्र में पनडुब्बी रोधी अभियान को मिलेगी ताकत

एजेंसी। चेन्नई

भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटरक्राफ्ट (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) परियोजना के सातवें पोत ‘अभय’ को लॉन्च किया गया। पोत का निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता ने किया है और इसे एलएण्डटी, कट्टपल्ली में लॉन्च किया गया।

यह परियोजना भारतीय नौसेना की तटीय जलक्षेत्र में पनडुब्बी रोधी क्षमता मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। करीब 77 मीटर लंबे इन पोतों की अधिकतम गति 25 नॉट और परिचालन क्षमता करीब 1,800 समुद्री मील है। इन्हें तटीय जलक्षेत्र में पनडुब्बी रोधी



अभियानों के साथ कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और समुद्री सुरंग बिछाने जैसे कार्यों के लिए तैयार किया गया है। पोतों में हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी एंटी-सबमरीन रॉकेट और शैलो वॉटर सोनार जैसी प्रणालियां लगाई गई हैं। परियोजना में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा

है, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। एएसडब्ल्यू शैलो वॉटरक्राफ्ट का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाना और उनसे निपटना है। इन पोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता और तटीय निगरानी व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

बीएमडब्ल्यू में 2027 तक 8 हजार नौकरियां घटाने की तैयारी

चीनी बाजार में कमजोर बिक्री और बढ़ती प्रतिस्पर्धा का असर; प्रशासनिक व विकास विभागों पर कटौती का ज्यादा प्रभाव

एजेंसी। बर्लिन

जर्मनी की लगजरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू 2027 के अंत तक करीब 8,000 नौकरियां कम करने की तैयारी में है। कंपनी और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के तहत यह कटौती स्वीच्छक सेवानिवृत्ति और कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने के बाद पदों को नहीं भरने के जरिए की जाएगी।

प्रस्तावित कटौती मुख्य रूप से प्रशासन और विकास से जुड़े विभागों में होगी, जबकि उत्पादन क्षेत्र के कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। यह कदम कंपनी के लागत घटाने और संगठन को अधिक दक्ष बनाने की योजना का हिस्सा है।

बीएमडब्ल्यू पर सबसे बड़ा दबाव चीन के बाजार में कमजोर प्रदर्शन का है। कंपनी की दूसरी तिमाही में चीन में वाहन बिक्री करीब 30 प्रतिशत घटने की खबर है। चीन की कंपनियों



से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से बदलती तकनीक और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता ने भी कंपनी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। जून में बीएमडब्ल्यू ने 2026 के लिए अपने मुनाफे के अनुमान को भी घटाया था।

लागत घटाने पर जोर: बीएमडब्ल्यू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलान नेडेल्जकोविच ने

कंपनी की लागत और दक्षता सुधारने की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया है। कंपनी का लक्ष्य बदलते वैश्विक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहना है। हालांकि, प्रस्तावित कटौती का असर उत्पादन कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा और कंपनी ने इसे बड़े पैमाने पर स्वीच्छक कार्यक्रम के जरिये लागू करने की योजना बनाई है। जर्मनी का वाहन उद्योग इस

समय चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। बीएमडब्ल्यू से पहले कई यूरोपीय वाहन कंपनियों की कर्मचारियों की संख्या घटाने की योजनाएं घोषित कर चुकी हैं। ऐसे में बीएमडब्ल्यू का फैसला पूरे जर्मन वाहन उद्योग में जारी पुनर्गठन की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने वाला अमेरिकी आतंकवाद के आरोपों में भी दोषी

एजेंसी। न्यूयॉर्क

लेखक सलमान रुश्दी पर 2022 में चाकू से हमला करने वाले अमेरिकी नागरिक हदी मातर को अमेरिका की संघीय अदालत की जुरी ने आतंकवाद से जुड़े सभी आरोपों में दोषी ठहराया है। 28 वर्षीय मातर को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े आतंकवादी कृत्य और आतंकवादियों को सामग्री सहायता देने समेत आरोपों में दोषी पाया गया। जुरी ने करीब दो घंटे विचार-विमर्श के बाद फैसला सुनाया। मातर पहले ही न्यूयॉर्क की एक अदालत में हत्या के ग़यास के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और 25 साल की सजा काट रहा है। संघीय मामले में उसे उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। 2022 में न्यूयॉर्क के चॉटोकवा



संस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान मातर ने रुश्दी पर चाकू से हमला किया था। रुश्दी को करीब 15 बार चाकू मारा गया था, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आईं। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि मातर ने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला रुहोल्लाह खामेनेई की 1989 की फतवे जैसी

घोषणा से प्रेरित होकर हमला किया था। मातर की संघीय मामले में सजा पर सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित है। दोषसिद्धि के बाद उसे संघीय स्तर पर भी लंबी सजा का सामना करना पड़ सकता है। रुश्दी ने मुकदमे के दौरान अदालत में गवाही देते हुए हमले और उसके बाद अपने स्वास्थ्य पर पड़े असर के बारे में बताया था।

एजेंसी। नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 38 वर्षीय रहाणे ने कहा कि अब उनके लिए आगे बढ़ने और जिंदगी के नए पड़ाव की ओर जाने का सही समय है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को विराम दिया। रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 एकदिवसीय और 20 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। उनका अंतरराष्ट्रीय करियर 2013 में शुरू हुआ था। रहाणे के करियर का सबसे यादगार अध्याय 2020-21 का ऑस्ट्रेलिया दौरा रहा। एडिलेड टेस्ट में भारतीय टीम महज 36 रन



पर सिमटने के बाद कप्तान विराट कोहली की गैरमौजूदगी में रहाणे ने टीम की कमान संभाली। मेलबर्न में उन्होंने हवाब के बीच 112 रन की शानदार पारी खेली और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

अमेरिका ने विदेशी ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर लगाई रोक, सुरक्षा खतरे का दिया हवाला

चीन ने जताई आपत्ति, कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीनी कंपनियों को निशाना बनाना गलत

एजेंसी। वॉशिंगटन

अमेरिका ने नए विदेशी निर्मित ह्यूमनॉइड और चार पैरों वाले उन्नत रोबोटों के आयात पर रोक लगा दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों का हवाला दिया है।

आशंका है कि ऐसे रोबोटों के जरिये संवेदनशील जानकारी जुटाई जा सकती है या महत्वपूर्ण ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। प्रतिबंध का असर खास तौर पर चीन की रोबोट कंपनियों पर पड़ने की संभावना है, जो इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हालांकि, पहले से अमेरिका में मौजूद या पहले मंजूरी पा चुके रोबोट इस रोक के दायरे में नहीं होंगे।

चीन ने अमेरिकी फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा



की आड़ में चीनी उत्पादों और कंपनियों के साथ भेदभाव करना गलत है। चीन ने अमेरिका से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंध जारी रहा तो वह जवाबी कदम उठा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों और सांसदों का कहना है कि चीन में विकसित रोबोट और स्वायत्त तकनीकें अमेरिकी महत्वपूर्ण ढांचे, सरकारी नेटवर्क और संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। अमेरिकी संसद में भी चीनी रोबोटों से जुड़े संभावित

गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों पर चर्चा हो चुकी है। दूसरी ओर, चीन का कहना है कि अमेरिका बार-बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चीनी तकनीकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब चीन ह्यूमनॉइड रोबोट के क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा है।

चीनी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 400 से अधिक पूर्ण ह्यूमनॉइड रोबोट उत्पाद विकसित किए जा चुके हैं, जो दुनिया के कुल ऐसे उत्पादों के आधे से अधिक हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीओके को बताया ‘पाकिस्तानी कश्मीर’, भारत ने जताई आपत्ति

अमेरिका में भारतीय दूतावास ने शब्दावली को बताया भ्रामक, कहा- पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा

एजेंसी। नई दिल्ली

अमेरिका के प्रमुख समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के लिए ‘पाकिस्तानी कश्मीर’ शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है।

अमेरिका में भारतीय दूतावास ने इस शब्दावली को भ्रामक बताते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर का वह हिस्सा, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत लगातार पाकिस्तान पर इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाता रहा है।

भारतीय दूतावास ने कहा कि संवेदनशील भू-राजनीतिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते समय तथ्यों और स्थापित स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूतावास की



आपत्ति ऐसे समय आई है, जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रिपोर्टिंग हो रही है। भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर

के पूरे क्षेत्र पर उसका संवैधानिक और कानूनी दावा है और पाकिस्तान ने इसके एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से के लिए ‘पाकिस्तान अधिभूत

जम्मू-कश्मीर’ या ‘पीओके’ शब्द का इस्तेमाल करता है। वहीं, पाकिस्तान इस क्षेत्र को ‘आजाद जम्मू-कश्मीर’ कहता है। दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है।

जापान में भूकंप से अब तक 30 की मौत, मॉल के मलबे में रेस्क्यू जारी

एजेंसी। टोक्यो

जापान के दक्षिणी क्यूशू द्वीप में आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। शुरुआती रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 28 बताई गई थी। कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं। काशिमा स्थित एक शॉपिंग मॉल का हिस्सा ढहने के बाद वहां फंसे लोगों की तलाश में राहत और बचाव दल लगातार मलबा हटा रहे हैं। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं।

भूकंप प्रभावित इलाकों में तेज गर्मी के बीच राहत कार्य जारी है। कई इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई है, जबकि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बचाव दल मलबे में किसी जीवित व्यक्ति के फंसे होने की संभावना को देखते



हुए सावधानी से अभियान चला रहे हैं। क्षेत्र में आए एक और झटके ने भी बचाव कार्य को चुनौतीपूर्ण बनाया है।

बड़े उद्योगों पर भी असर: भूकंप के बाद क्षेत्र में कई प्रमुख कंपनियों ने सुरक्षा कारणों से अपने संयंत्रों में काम अस्थायी रूप से रोक दिया है। कुमामोटो क्षेत्र जापान के वाहन और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिकारियों का कहना है कि

प्राथमिकता राहत एवं बचाव कार्यों के साथ प्रभावित लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाना है। काशिमा के प्रभावित शॉपिंग मॉल में बचाव दल लगातार मलबे की जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक घटनाक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। बाद में राहत दलों ने कई लोगों को बाहर निकाला, लेकिन मलबे के भीतर संभावित पीड़ितों की तलाश जारी रही। प्रशासन ने नुकसान का व्यापक आकलन शुरू कर दिया है।

लिटन दास बने बांग्लादेश वनडे टीम के नए कप्तान

एजेंसी। ढाका

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिटन दास को वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। वह 2027 वनडे विश्व कप तक 50 ओवर की टीम की अगुआई करेंगे। लिटन पहले से ही बांग्लादेश की टी-20 टीम के कप्तान हैं।

उनके वनडे कप्तान बनने के साथ अब टीम में दो कप्तानों की व्यवस्था होगी। नजमुल हुसैन शांतो टेस्ट टीम की कमान संभालते रहेंगे, जबकि लिटन दास वनडे और टी-20 टीम का नेतृत्व करेंगे। यह फैसला 2027 विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मेहदी हसन मिराज को वनडे कप्तानी से हटाया गया है। लिटन दास को सीमित ओवरों के दोनों प्रारूपों की जिम्मेदारी देने का फैसला टीम में नेतृत्व की एकरूपता लाने के उद्देश्य से किया गया है।

बरनाला लाठीचार्ज के विरोध में लुधियाना में दिखा बंद का असर, जगह-जगह प्रदर्शन

वाल्मीकि समाज ने शांतिपूर्ण ढंग से बंद कराए बाजार, सरकार से की दोषी पुलिस कर्मियों पर कारवाई की मांग

अश्वनी पाहवा | लुधियाना
समर न्यूज

बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में वीरवार को बुलाए गए पंजाब बंद का असर औद्योगिक नगरी लुधियाना में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। वाल्मीकि समाज के लोगों ने शहर के विभिन्न इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से रैलियां और प्रदर्शन किए।

इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने बाजारों में पहुंचकर व्यापारियों से बंद का समर्थन करने की अपील की, जिस पर बड़ी संख्या में दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। पूरे दिन शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई।

सुबह से ही वाल्मीकि समाज के सदस्य विभिन्न बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों को बरनाला की घटना की जानकारी देते हुए बंद में सहयोग



पूर्व चेयरमैन डॉ. डी.पी. खोंसला ने दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई की मांग की प्रदर्शन में शामिल भाजपा पंजाब के सीनियर नेता पूर्व चेयरमैन डॉ. डी.पी. खोंसला ने कहा कि सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। यदि प्रदर्शनकारियों के साथ बल प्रयोग हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से प्रभावित कर्मचारियों को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

करने की अपील की। समाज के नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और किसी भी दुकानदार पर जब्तन दुकान बंद कराने का दबाव नहीं बनाया गया।

प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और बरनाला में हुए कथित लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग उठाई गई। बंद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क

प्रमुख बाजार रहे बंद

पंजाब बंद के दौरान लुधियाना के मुख्य बाजार चौड़ा बाजार, चुमार मंडी, केसर गंज मंडी, तालाब बाजार, अकालगढ़ मार्किट, मीणा बाजार, माल रोड, किप्पस मार्किट, सराभा नगर, जमालपुर मार्किट, रेखी सिनेमा रोड, गांधी मार्किट, करीमपुरा बाजार, फील्ड गंज, फिरोज गांधी मार्किट, हैबोवाल मार्किट, सहित अन्य सभी बाजार बंद रहे।

शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखी।

दिनभर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रही। शाम तक प्रदर्शन समाप्त होने के बाद बाजारों में धीरे-धीरे सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गईं।

हेरोइन, देसी पिस्तौल और कारतूस सहित एक युवक गिरफ्तार

सहजप्रीत सिंह | लुधियाना
समर न्यूज

शहर में नशा तस्करो और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मोती नगर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन, दो देसी पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 29 जुलाई को एसआई सेटी कुमार अपनी टीम के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे।

इसी दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि कैलाशा नगर निवासी बिट्टू कुमार हेरोइन बेचने का धंधा करता है तथा उसके पास अवैध हथियार भी हैं। सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस टीम ने कैलाश नगर स्थित मंगा किरयाना स्टोर के निकट घेराबंदी कर आरोपी बिट्टू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन, दो देसी पिस्तौल .32 बोर और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

थाना मोती नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर नंबर 182, दिनांक 29 जुलाई 2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 61 व 85 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया है।

दो घंटे की बारिश... और ‘स्मार्ट सिटी’ की हकीकत सड़क पर तैरती दिखी

कूड़ा बहा, सड़कें धँसीं, गड्ढों में समाई गाड़ियां, जलभराव ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल

लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज

महज दो घंटे की बारिश ने गुरुवार को लुधियाना की ‘स्मार्ट सिटी’ की तस्वीर बदलकर रख दी। शहर की प्रमुख सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, कई इलाकों में जलभराव से यातायात ठप पड़ गया और निगम के दावों की हकीकत लोगों के सामने आ गई। लोगों का कहना था कि अगर दो घंटे की बारिश ही शहर की रफ्तार रोक दे, तो आखिर स्मार्ट सिटी के दावों का आधार क्या है।

बारिश ने नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान सफाई व्यवस्था की पोल भी खोल दी। कई दिनों से नहीं उठाए गए कूड़े के ढेर बारिश के पानी के साथ सड़कों पर बहने लगे। नालियां जाम हो गईं और गंदा पानी सड़कों पर भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।

बारिश के दौरान बाबा थान सिंह चौक स्थित एक पुरानी इमारत का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय वहां कोई राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल रहा। वहीं हीरो चौक के पीछे सड़क धंसने से घर के बाहर खड़ी एक कार अचानक गहरे गड्ढे में समा गई। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य



हर बारिश में वही हाल, समाधान अब भी नहीं लुधियाना में लगभग हर बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया। करोड़ों रुपये की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और ड्रेनेज सुधार के दावों के बावजूद शहर की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं दिख रहा। गुरुवार की बारिश ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि यदि महज दो घंटे की बारिश शहर की व्यवस्था को ठप कर सकती है, तो आखिर स्मार्ट सिटी का दावा किता मजबूत है?

चलाकर कार को बाहर निकाला। इस घटना ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए। मॉडल टाउन में पहले से बने बड़े-बड़े गड्ढे बारिश के पानी में पूरी तरह छिप गए। वाहन चालकों को सड़क का अंदाजा नहीं लग सका, जिसके कारण कई दोपहिया और चारपहिया वाहन गड्ढों में फंस गए। कई स्थानों पर वाहन पलटने की घटनाएं भी सामने आईं।

उधर सरगोधा कॉलोनी में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य बारिश के कारण मुसीबत बन गया। खुदाई वाली जगह की मिट्टी दलदल में बदल गई, जिससे सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां मिट्टी में धंस गईं। लोगों को वाहनों को बाहर

हड़ताल की देहरी मार

नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल का असर शहर की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई दिया। कई इलाकों से कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाया गया। कूड़ा उठाने वाले कंपैक्टर भी बंद रहे, जिससे सड़कों और बाजारों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए। बारिश शुरू होते ही यही कूड़ा पानी के साथ बहकर नालियों में पहुंचा और जलनिकासी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई।

निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

पंजाबी फिल्म ‘मेरा यार गवाचा’ का ऑफिशियल पोस्टर हुआ जारी

माही म्यूजिक के बैनर तले बन रही फिल्म, अगले साल होगी रिलीज
समर न्यूज | लुधियाना

पंजाबी फिल्म “मेरा यार गवाचा” की आधिकारिक घोषणा और पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है। बेहतरीन अभिनेता हरीश वर्मा और दीप सहगल की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस प्रोजेक्ट को ‘माही म्यूजिक’ के प्रमुख बैनर तले बनाया जा रहा है। “मेरा यार गवाचा” एक ‘स्लाइस-ऑफ़-लाइफ़’ ड्रामा और रोमांटिक फिल्म है जो कई समकालीन सामाजिक मुद्दों को उठाती है। पारंपरिक प्रेम कहानी के बजाय, यह फिल्म रिश्तों में आज के दौर की कशमकश को दिखाती है और दो अलग-अलग पीढ़ियों के बीच की दूरी को कम करती है।

फिल्म का मकसद दर्शकों में पुरानी यादें ताजा करना है, उन्हें कॉलेज और हॉस्टल की उन पुरानी दोस्ती की याद दिलाना जो रोमांमर्रा की ज़िंदगी की भागदौड़ में कहीं खो गई थीं। “मेरा यार गवाचा” में हरीश वर्मा



और दीप सहगल मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस प्रोजेक्ट का निर्देशन प्रवीण कुमार कर रहे हैं और यह लेखक अमन सिद्ध की दिलचस्प कहानी पर आधारित है। फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप कुमार और पूनम कुमारी हैं, जिन्हें एंजीक्यूटिव प्रोड्यूसर संदीप सिंह और अमन का सहयोग मिल रहा है। फिल्म के विजुअल और सिनेमैटोग्राफी को डायरेक्टर ऑफ़ फ़ोटोग्राफी सोनी सिंह ने तैयार किया है।

श्री सिद्धपीठ श्री दंडी स्वामी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव

पंचामृत अभिषेक, यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन और भजनों से भक्तिमय हुआ वातावरण

लक्की भट्टी | लुधियाना
समर न्यूज

सिविल लाइन स्थित श्री सिद्धपीठ श्री दंडी स्वामी मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा (व्यास पूजा) महोत्सव श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव के साथ पंडित राज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और हजारों भक्तों ने श्री दंडी स्वामी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

महोत्सव का शुभारंभ प्रातःकाल पारंपरिक झंडा रस्म के साथ हुआ। इसके उपरांत श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री शिव परिवार एवं श्री दंडी स्वामी महाराज का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पंचामृत से भव्य अभिषेक एवं विशेष पूजन किया गया। महाआरती के दौरान गुरु मंदिर “जय गुरुदेव” के जयघोष से पूरा उठा और प्रथम दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को



धन्य महसूस करते नजर आए। इसके बाद गढ़दीवाला (पंजाब) से पधारे पंडित सुदेश शर्मा ने वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार विशेष पूजन संपन्न करवाया। वहीं, बनारस से पधारे श्री दंडी स्वामी महाराज के प्रपौत्र मुकुल पांडे एवं मंदिर के अध्यक्ष पंडित राज कुमार शर्मा ने श्री गुरु महाराज का विधिवत पूजन एवं वंदन किया।

दोपहर से लेकर सायंकाल तक आयोजित हरिनाम संकीर्तन में पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। सिद्धपीठ परिवार के केशव जोशी, विशाल अरोड़ा, हरियाल आहूजा, अश्वनी ग्रोवर, बृजमोहन ढींगरा, सुनील कालिया, सोमनाथ



बब्बू, ललित शर्मा, पंडित दीपक शर्मा, राघव उप्पल, संदीप लांबा, आत्म प्रकाश,माधव नागर एवं माधव कालरा सहित अन्य भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक गुरु महिमा से ओत-प्रोत भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मंदिर के अध्यक्ष पंडित राज कुमार शर्मा ने सभी श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का अत्यंत पावन पर्व है। इस दिन प्रत्येक शिष्य अपने गुरु का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। महोत्सव के समापन पर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया।

मत्कड़ परिवार ने माता-पिता की स्मृति में कराया कथा-कीर्तन समागम

नील कमल | लुधियाना
समर न्यूज

गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, मॉडल ग्राम में मक्कड़ परिवार द्वारा अपने स्वर्गीय माता-पिता की वार्षिक पुण्य स्मृति को समर्पित कथा-कीर्तन समागम का आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति भाव से किया गया।

समागम का आयोजन सरदार जसपाल सिंह जा, सरदार भूपिंदर सिंह एवं सरदार कंवलजीत सिंह बिट्टू मक्कड़ परिवार की ओर से

किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कथावाचक भाई साहिब भाई पिरपाला सिंह ने गुब्बानी के दिव्य संदेशों का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए संगत को गुरु घर से जुड़े रहने और गुरुमत के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। समागम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर गुरु की वाणी का रसगान किया।

इस अवसर पर सरदार अरविंदर पाल सिंह बंटी ने संगत को अपने माता-पिता द्वारा दिए गए संस्कारों एवं शिक्षाओं को जीवन में अपनाने



का संदेश दिया। समागम के समापन पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से भाई साहिब भाई पिरपाला सिंह तथा मक्कड़ परिवार का सम्मान किया गया। सम्मान करने वालों में

प्रधान सरदार जतिंदर सिंह गलहोतरा, सरदार हरभजन सिंह सचदेवा, सरदार अरविंदर पाल सिंह बंटी, सरदार हरविंदर मोहन सिंह खालसा, सरदार परमजीत सिंह, सरदार जसवीर सिंह

श्रद्धा सच्ची आस्था और गुरु के आशीर्वाद से होता है जीवन का बेड़ा पार : सुनील जिंदल गुरु पूर्णिमा पर श्री बालाजी की चौकी में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

अश्वनी पाहवा | लुधियाना
समर न्यूज

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री बालाजी सेवा संघ और बालाजी सेवा परिवार की ओर से लक्ष्मी नारायण मंदिर, भाई रणधीर सिंह नगर में श्री बालाजी महाराज की विशाल चौकी का आयोजन किया गया।

चौकी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरु मां सुनील जिंदल ने की। चौकी की शुरुआत से पहले उन्होंने अपने गुरु मेहदीपुर बालाजी महाराज और बाबा संत राम जिंदल



के स्वरूप को फूल-माला अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद ज्योति प्रचंड कर और पुष्प वर्षा के साथ चौकी का शुभारंभ किया गया। श्री बालाजी सेवा संघ और बालाजी सेवा परिवार के सदस्यों ने भी अपने गुरु बाबा जिंदल की आरती कर उन्हें पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर बांबी जिंदल, शिव नारायण

गुप्ता, सतीश मल्होत्रा और अशोक सिंघानिया ने बालाजी महाराज को पुष्प माला भेंट कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से लुधियाना भाजपा प्रधान सुनील मौदगिल, आशीष गुप्ता और अंकित गर्ग भी पहुंचे और बालाजी महाराज के चरणों में नमन किया। इस मौके पर सुनील मौदगिल ने कहा कि माता-

पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती और बच्चों के प्रथम गुरु उनके माता-पिता ही होते हैं। प्रसिद्ध भजन गायक महंत सुनील रावत एंड पार्टी तथा जप मान पटियाला वालों ने अपने मधुर भजनों से संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया।

गुरु मां सुनील जिंदल ने कहा कि सच्चा गुरु ही मनुष्य को भव सागर से पार लगाता है। उन्होंने सभी के अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की। लक्ष्मी नारायण मंदिर कमेटी की ओर से बालाजी महाराज को छप्पन भोग और लंगर प्रसाद की सेवा की गई। मेहदीपुर से लाए गए विशेष जल के छोटों की वर्षा भी श्रद्धालुओं पर की गई।